

MR. CHAIRMAN : The question is :
"That the Bill, as amended, be
passed."

The motion was adopted

MR. CHAIRMAN : The House will
now take up the next item.

15.12 hrs.

[SHRI M. B. RANA in the Chair].

SHRI S. M. BANERJEE : Sir, I have
a submission to make. We do not know
what happened in the House. There was
no Third Reading and the Bill has been
declared as passed.

MR. CHAIRMAN : The Bill has
been passed and we cannot now go back.

15.03 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE : CENTRAL SALES TAX
(AMENDMENT) ORDINANCE
AND
CENTRAL SALES TAX
(AMENDMENT) BILL

श्री यज्ञ वल्लभ शर्मा (अमृतसर) : सभापति
महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूँ :

"यह सभा केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन)
अध्यादेश, 1969 (1969 का अध्यादेश
संख्या 4) का, जो राष्ट्रपति के रूप में
कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा 9
जून, 1969 को प्रख्यापित किया गया
था, निरनुमोदन करती है।"

मैं इस समय 9 जून, 1969 को जारी किये
गये अध्यादेश का, जो केन्द्रीय विक्रय कर अधि-
नियम (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में है,
विरोध करने के लिए खड़ा हुआ है। यह
अत्यन्त खेद का विषय है कि प्रायः सरकार

अध्यादेशों के द्वारा ही अपना काम चलाने की
कोशिश करती रही है। इस विक्री कर के कारण
जो केन्द्र द्वारा लगाया जा रहा है, व्यापारियों
को और प्रशासनिक ढांचे में जितनी कठिनाइयां
आ रही हैं उसी के आधार पर मैं इसका विरोध
करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वास्तव में प्रदेशों
के अन्दर इस प्रकार का विक्रीकर लागू हो जाने
के बाद केन्द्र द्वारा यह विक्री कर लागू नहीं
करना चाहिये था। जीवन उपभोग की बुनियादी
वस्तुओं के ऊपर अनेक प्रकार के मुद्दों पर बार
बार कर लगाने की जो व्यवस्था है, उसके
कारण से आम व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी
कठिनाई है। अभी सरकार के इस गलत कानून
का, जो सरकार ने 1966 में लागू किया था,
सुप्रीम कोर्ट द्वारा यद्दालम केस के अन्दर विरोध
किया गया है, और उसके कारण से सरकार
को वसूल की गई रकमों व्यापारियों को वापस
करनी पड़ रही है। लेकिन इस संशोधन के
द्वारा सरकार उस कानून को फिर ला रही है।
मैं समझता हूँ कि हड़बड़ाहट के अन्दर गलत
किस्म के कानून बनाना और गलत कानूनों को
आगे जाकर बड़ी अदालतों में चैलेंज होना, फिर
उन कानूनों के प्रति जनता के अन्दर अश्रद्धा पैदा
होना, जनता के अन्दर कानून के प्रति आदर
और सत्कार की भावना को कम करने वाली
कोशिश सरकार की है। अगर सरकार सूझ
समझ के साथ, ऊंचे दर्जे के और अच्छे प्रकार
से ड्राफ्ट किए हुए कानून बनाये, भले ही थोड़े
कानून बनाये, जिनके द्वारा जीवन की व्यवस्था
हो सके, तो लोगों के अन्दर कानून के प्रति
आस्था पैदा होगी और वह कानून जन जीवन
को नित्य प्रति के जीवन की प्रक्रिया में सुविधा
देंगे। यहां सोने के सम्बन्ध में जब कानून बनाया
गया था तब उस समय भी हमने सरकार से
कहा था कि इस प्रकार का कानून न बनाइये
जिसकी एक-एक धारा को चुनौती मिले देश के
न्यायालयों के अन्दर। लेकिन तब सरकार नहीं
मानी। आज वही चीज इस कानून के सम्बन्ध
में हो रही है। गलत प्रकार के कानून बनाये

जाते हैं इसलिए उनका पालन करने की स्थिति में जनता नहीं रहती। उन्हीं गलत कानूनों के आधार पर नौकरशाही, जिससे उन कानूनों का सम्बन्ध रहता है उस जन-जीवन के अन्दर कठिनाई पैदा करती है। इस प्रकार के गलत कानून नहीं बनाये जाने चाहियें। सरकार अपने विधि मंत्रालय के अन्दर इन कानूनों को अच्छी तरह से ड्राफ्ट करवाये ताकि उससे हमको कठिनाई न पैदा हो।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि सरकार अब यह संशोधन ला रही है कि बारह साल पीछे तक इस कानून का प्रभाव पड़ेगा, यानी इसका रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट होगा, 1 जुलाई, 1956 तक यह चीज जायेगी। आप अनुमान लगाइये कि व्यापारियों को इसके कारण कितनी कठिनाई होगी। व्यापारियों के जीवन में पिछले बारह वर्षों में कितने उतार चढ़ाव रहे और उनके कारण व्यापार की स्थिति न जाने क्या से क्या हो चुकी है। कितने ही व्यापारी मार्केट से उठ गये होंगे और कितने ही व्यापारियों के धन्धों की रूपरेखा बदल गई होगी। लेकिन इस कानून की धाराओं से उन सभी लोगों को कठिनाई पैदा होगी। इसमें निस्सन्देह यह कहा गया है कि जिन बड़े व्यापारियों ने अपने छोटे कस्टमर्स से कर वसूल नहीं किया है, उनसे इस कर की वसूली नहीं की जायेगी। लेकिन नौकरशाही तो उनको यह नहीं बतलायेगी।

मैं आपके द्वारा सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि सेल्स टैक्स का जो प्रशासनिक ढांचा है वह जिस तरह से आम व्यापारी के साथ बर्ताव करता है, जिस तरीके से आम व्यापारी के साथ डील करता है, वह उन लोगों के लिए मुश्किल पैदा करने वाला है। उनके द्वारा व्यापारियों का इतना ज्यादा हैरेसमेंट होता है कि वह बेचारे उस नौकरशाही से डरे और सहमे हुए रहते हैं। मैं यह नहीं कहता कि व्यापारी सोलह आने ईमानदार होते हैं, लेकिन

इस सम्बन्ध में प्रशासनिक ढांचे की हैडलिंग ऐसी है कि वह व्यापारी को मूलतः बेईमानी समझ कर ही उनके साथ बर्ताव करता है। उनका दुगुना-चौगुना असेसमेंट कर दिया जाता है और तय कर दिया जाता है कि इतना तो उन्होंने वसूल किया ही होगा, और उसके बाद उनके साथ सोदा किया जाता है। यह इस प्रकार का प्रावधान इसके अन्दर किया जा रहा है जिसके अनुसार सरकार 12 साल पूर्व के विक्री करों की वसूली करेगी। सरकार जो धन लौटा चुकी है उन मुद्दों पर भी सरकार वसूली करेगी, इसके कारण नौकरशाही को भ्रष्टाचार करने का मौका मिलेगा और आम व्यापारी को इसके कारण कठिनाई आयेगी। इसलिए मैं इसका भी विरोध करता हूँ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि अनेक प्रकार के कानून बनाने के वजाय इन करों के सम्बन्ध में सरकार कोई थोड़ी और सुविधा देने वाली चीज लाये, सिम्प्लीफाइड ढंग के कानून सरकार बनाये। आज कोई भी व्यापारी बिक्री कर देने से इन्कार नहीं करता, लेकिन मुश्किल की बात यह है कि एक ही प्रकार के पदार्थ पर चार-चार स्थानों पर कर लगाया जाता है। यह जो मल्टिपल प्वाइंट टैक्स लगाया जा रहा है उसके कारण व्यापारी को बड़ी मुश्किल है। जिम प्रकार से हमने तम्बाकू पर, खाण्ड पर और बाकी पदार्थों पर उत्पादन के स्थान पर ही एक्साट्रज ड्यूटी लगा दी है, उसी तरह किसी एक स्थान पर आरम्भ से लेकर अन्त तक सेल्स टैक्स लगा दिया जाय और उसके मुताबिक भाव रख कर काम हो, ताकि व्यापारी को इसके कारण कठिनाई पैदा न हो। सरकार अगर सेल्स टैक्स को किसी एक प्वाइन्ट के ऊपर ही वसूल करने की व्यवस्था कर दे तो इससे आम व्यापारी को राहत मिलेगी। मैं कहूँगा कि सरकार को करों के सम्बन्ध में ऐसी नीति अपनानी चाहिये जैसे मधु मक्खी फूलों का रस तो प्राप्त कर लेती है लेकिन किसी फूल अथवा पत्त

[श्री यज्ञदत्त शर्मा]

का रूप और रंग नहीं बिगाड़ती है। परन्तु हमारी सरकार शायद वसूली थोड़ी करती है लेकिन खर्चा ज्यादा कर देती है। यहां दिल्ली की मिसाल मैं देता हूँ। साइकल टैक्स यहां लगा हुआ है। इस टैक्स से वसूली थोड़ी होती थी लेकिन वसूली करने वाला जो ढांचा था उसके ऊपर खर्चा ज्यादा हो जाता था। इससे आम आदमी को, उपभोक्ता को मुश्किल भी होती थी। हमने दिल्ली प्रशासन में आते ही इसको खत्म किया। हमें गाली तो जरूर दी जा रही है लेकिन आम आदमी को इससे राहत मिली है और प्रशासनिक ढांचे पर जो दबाव था वह कम हुआ है और सरकारी खर्च में कमी हुई है। इससे दिल्ली की अर्थ-व्यवस्था को भी लाभ हुआ है। मैं चाहता हूँ कि सरकार सूत्रबद्ध से काम ले। लेकिन सरकार मन्धर की तरह से लेती थोड़ा है लेकिन घेरा ज्यादा बना देती है जिसके कारण खुजली और तड़प पैदा होती है।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी एक ही प्वाइंट पर ले लेती है उसी तरह से इस कर के बारे में भी सोचे। मैं चाहता हूँ कि आम व्यापारी को इन टैक्सों के कारण मुश्किल में न डाला जाए और प्रशासनिक ढांचे को भ्रष्ट होने से बचाया जाए। प्रशासनिक ढांचे को ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिये जिससे वह व्यापारी को तंग कर सके।

MR. CHAIRMAN : Resolution moved:

"This House disapproves of the Central Sales Tax (Amendment) Ordinance, 1969 (Ordinance No. 4 of 1969) promulgated by the Vice-President acting as President on the 9th June, 1969."

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C.
SETHI) : Mr. Chairman, Sir, I beg to
move* :

"That the Bill further to amend the Central Sales Tax Act, 1956 and to provide for certain other matters, be taken into consideration."

The hon. Member Shri Yajna Datt Sharma has raised objection to the manner in which this Ordinance was promulgated. As far as this Ordinance is concerned, this was necessitated on account of the Supreme Court judgment in the case of Yaddalam Lakshminarasimhiah Setty and Sons. According to this judgment, the sales tax levied by the various States in the form of inter-State sales tax was nullified. This would have resulted into a very heavy drain on the State Governments and, therefore, it was necessary that we should come forward with an Ordinance and that is why it was promulgated.

According to this judgment, it was held by the court that the expression "levied" in Section 9 (1) of the Sales Tax Act, 1956 meant "levied" as under the appropriate State law. This was one point where the Supreme Court gave their judgment, that is, with regard to the tax which was to be levied according to the Sales Tax Act which was prevalent in a particular State.

Apart from this, the Supreme Court also held in this very case that this also meant the necessary change into the mode of computing the tax with the result that it meant a very heavy drain on the State Governments. Therefore, we had to take recourse to various regional committees who were to give us advice on this point and the various State Governments were also consulted. Ultimately, it was the State Governments who approached the Central Government that an Ordinance had to be promulgated and that, otherwise, the State Governments will have to bear a burden of about Rs. 70 crores to Rs. 75 crores.

The hon. Member has raised another issue as to whether the sales tax should be a single-tax or multi-tax or a single-point tax. That is a different aspect altogether. As far as this particular Bill is concerned, this is only to replace the Ordinance which was promulgated.

*Moved with the recommendation of the Vice-President acting as President.

As far as the inter-State sales tax is concerned, under article 269 (1), this does not accrue to the Central Government. This is purely a measure by which the State Governments get the entire proceeds of the collection. This is on sales resulting in the movement of goods from one State to another. Therefore, it was necessary that the ways and means of the State Governments did not go from bad to worse and that is why this was necessitated.

As far as the determination and turnover of the tax is concerned, we have made it abundantly clear now, in this particular Bill, that this would be the Central sales tax according to which it will be calculated and also where a particular State Government has law about the sales-tax in a particular matter, that will not come in the way and the tax will be levied both in regard to the manner and computation according to the provisions as stipulated in this particular Bill.

This is a very small measure, a very small Bill. At this particular moment I would not like to go into much details, but after the hon. members have moved their amendments and brought forward their points, I would be in a position to state more clearly as to what are the details of this particular measure. Sir, I move.

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill further to amend the Central Sales Tax Act, 1956, and to provide for certain other matters, be taken into consideration."

Both the Statutory Resolution and the Motion are before the House. There are some amendments. Is Mr. Shiva Chandra Jha moving ?

SHRI SHIVA CHNDRA JHA (Madhubani) : Yes.

MR. CHAIRMAN : Mr. Abdul Ghani Dar.

SHRI ABDUL GHANI DAR : (Gurgaon) : Yes. I am also moving.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 1st November, 1969." (8)

SHRI ABDUL GHANI DAR : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st December, 1969." (9)

"That the Bill further to amend the Central Sales Tax Act, 1956 and to provide for certain other matters be referred to a Select Committee consisting of 15 members, namely : —

- (1) Shri Syed Badrudduja
- (2) Sardar Buta Singh
- (3) Shri Surendranath Dwivedy
- (4) Shri Humayun Kabir
- (5) Shri S. M. Joshi
- (6) Dr. Karni Singh
- (7) Shri Ghayoor Ali Khan
- (8) Chaudhari Randhir Singh
- (9) Shri Rabi Ray
- (10) Shri A. S. Stigal
- (11) Shri Prakash Vir Shastri
- (12) Shri Raghuvir Singh Shastri
- (13) Shri Sheo Narain
- (14) Shri Atal Bihari Vajpayee
- (15) Shri Abdul Ghani Dar."

with instructions to report by the 31st October, 1969. (26)

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : I am not able to agree with the Minister entirely that we can ignore the nature and the effect of sales-tax on the people and on the economy. While we are considering the precise Bill, we must remember that sales-tax had been one of the greatest deterrents to the expansion of market, the expansion of industry. In this connection, the Minister's memory may be refreshed that while sales-tax formed 24 per cent of the tax revenues of the States in the First Plan, it formed 34 per cent in the Second Plan and at present 48 per cent of the total tax revenues of the States come from sales-tax. This sales-tax was imposed to make up for the loss on excise revenue. What has happened is that many States have reimpos-

[Shri Lobo Prabhu]

ed excise revenue having given up prohibition. That means, sales-tax continues side by side with what it was meant to replace. In addition to sales-tax, the goods pay the excise tax of Centre and also the octroi tax in many places. The result is that almost half of the price of our commodities, on an average, is paid to the Government. This is a very sad state of thing. While those who make the articles, those who trade in them, do not get more than half, Government, by sitting here and passing a law, is able to take half the value, not from the producer but from the actual consumer! This has to be realised by those who suffer from inflation. I would, therefore, suggest that in this background this particular measure that is before us must be considered. This measure attempts to correct an Act passed 12 years ago.

In the first place, although there is no explicit ban on retrospective effect being given to a legislation, it is a well considered principle, it is a principle accepted in most countries, that retrospective effect should not be given to fiscal measures. In respect of income-tax, special exemption is made upto 14 years. In respect of the other taxes, there is no such exemption, if Government pleads that limitation is of 30 years in respect of its civil claims, then that limitation must arise from the law. The limitation cannot go backward from a law which is sought to be passed giving effect retrospectively for 12 years. This is an important point because it goes against the Constitution and I would like the Minister to note it for reply how retrospective effect can be given to a tax for as long a period as 12 years. I have an amendment that retrospective effect may be for 3 years after the period of limitation whichever is shorter.

The second point is whether this retrospective effect should be given without regard to price adjustments and tax refunds which have taken place. Now when a tax is imposed the buyer normally charges a lower price because he has not got to pay the tax. But when you impose the tax 12 years retrospectively, how is he to make the price adjustment which he charged in the absence of the taxes. No doubt, the decision in respect of taxes begins with the Yeddalam case in 1964. But since from the

very beginning it was contested that the tax was not due, this adjustment could have taken place. The seller might have reduced his price in anticipation that no tax is due on it. It is not fair that he should now be asked to pay the tax when in his own calculations of price he did not include it before.

The second point is about the tax refund. Now after the Yeddalam case many parties filed suits and refunds were given by courts and were even paid by the State Governments. The question is: whether refunds given should now be recalled as per provision in the Act. A man to obtain that refund has to go court, has to engage lawyers, has to pay court fees and even if there was some allowance made, the position would not have been so bad. But it now looks as if the Government does not care whether the refund has been made or not and is insisting that these people pay the tax as was due. In this connection the Minister must remember—I am referring again to the Mysore State—that the inter-State commodities involved are largely agricultural commodities like arecanuts, coconuts, coffee, etc. Is it the intention of the Government to discourage production of these items by imposing or attempting to collect the tax for 12 years. On the one hand we see that the Government is going all out for agriculture Government is nationalising banks in order to obtain funds for agriculture. Here it looks as if you are determined to ruin those who are in the arecanut, the coconut and other agricultural trades and ruin those who produce these items and I would, therefore, like the Minister earnestly to consider how far this is fair to their own programme of encouraging and improving agriculture.

Thirdly there is a provision that notwithstanding any judgment this law will apply. Is it not a contempt of court? When they have passed judgments after considerable expenditure on the part of the parties and considerable thought on the part of the courts, is it all to go waste because you are now passing a law?

Lastly, as far as the Mysore State is concerned, as soon as they lost the Central contribution through the 3% tax, they raised their own tax in respect of these commo-

dities from 2 to 5%. They covered this. Now you are going to reward them further with another 3%. I would like the Minister note for reply whether when there is such recovery made by the State, any plea for compassion for the State Government all arises. May be Kerala Government did not do this and the Kerala Government has been slow about it. But the Kerala Government had the same opportunity. In any case the taxes of the Kerala Government are by no means low. My submission is that this Act is a bad Act.

SHRI B. P. MANDAL : (Madhipura)
 On a point of order. There is no quorum in the House.

MR. CHAIRMAN : The bell is being rung—Now there is quorum. The hon. member may proceed.

SHRI LOBO PRABHU : I would like the Minister to consider not disturbing the refunds already made. Secondly, I would like him to consider why the burden of proving that the tax has not been collected should be put on the tax payer from 1964 after the Yadalam case. This last provision is most unfair on the taxpayer, to ask him to prove the thing in the negative over a period of nearly 6 years.

These are very important minor concessions being asked. I do hope that this much would be conceded in order to save this measure from agitation and litigation. It has been said in this country that there is no taxation without litigation. The old principle of no taxation without representation does not hold good for the 20th century. I would like the Minister to satisfy the taxpayer to this extent that he is not again driven to litigation and that this unhappy development of no taxation without litigation is not allowed to occur in this particular case.

SHRI HIMATSINGKA (Godda) : As I could understand from the speech of the hon. Minister, it appears that certain States levied certain inter-stage sales tax and because of the judgement of the Supreme Court, they may be asked to refund such amount which might go the extent of Rs. 70-75 crores. If that be so, I have nothing to say. But as I read it, the new clause proposed in the Bill says that the dealer shall be liable to pay the tax.

"A dealer shall be liable to pay tax under this Act on a sale of any goods effected by him in the course of inter-State trade or commerce notwithstanding that no tax would have been leviable (whether on the seller or the purchaser) under the sales tax law of the appropriate State if that sale had taken place inside that State".

The scheme of the Central Sales Tax Act as is apparent from section 8 is this. Every dealer was liable to tax at certain rates in the case of sale to Government and in the case of sale to registered dealers and in the case of certain goods declared of special importance and the section provides the tax payable by a dealer on his turnover as mentioned therein. In the case goods other than declared goods it shall be calculated at the rate of ten per cent or at the rate applicable to the sale or purchase of such goods inside the appropriate State whichever is higher and for the purchase of making any such calculation any such dealer shall be deemed to be a dealer liable to pay tax under the sales tax law of the appropriate State. Notwithstanding anything contained in sub clause (1) of sub-section (2) the next sub-clause reads—if under the sales tax law of the appropriate State the sale or purchase, as the case may be, of any goods by a dealer is exempt from tax generally, or is subject to tax generally at a rate which is lower than three per cent whether called a tax or fee or any other name, the tax payable under this Act on its turnover in so far as the turnover or any part thereof relates to the sale of such good shall be nil, or as the case may be shall be calculated at the lower rate.

Therefore, if the sale in a State of any particular goods was exempt from sales tax there would be no central sales tax on such goods even if those goods move out of that State that appears to be the scheme of the Act. There were certain articles which were not liable to tax if the sale had taken place in the State and on such goods there will be no central sales tax also if the goods moved out of the State. If that section is amended according to the present Bill, the dealer shall be liable to pay tax on the sale of any goods effected by him in the course of inter State trade or com-

[Shri Himatsingka]

merce notwithstanding that no tax would have been leviable under the sales tax law of the appropriate State if the sale had taken place in that State. The provision that is now proposed goes beyond and does away with the provisions of the Central Sales Tax Act. The Supreme Court has held that the tax been realised wrongly. If the Government wants that that should not be refunded, that is one thing. But if the law now proposed gives the right to impose such tax for the last 12 years, the position will be intolerable. The hon. Minister should make the position clear whether what is intended is only to safeguard the question of refund of any tax that may have been collected and there is no right to levy fresh tax on any dealer for the last 12 years simply because of the present amendment. Otherwise, it is an absolutely dangerous powers that would be given to the States to levy tax for the last 13 years on sales which were not liable to any kind of tax. I expect the Minister to make the position clear.

SHRI R. K. BIRLA (Jhunjhunu) : Before I start speaking on this Bill, I should like to say something which is not so relevant to this Bill. I will take two or three minutes only in this connection. My feeling is that we Independents, except elderly people like Shri Krishna Menon and Acharya Kripalani, are considered to be second-class Members of this House. This is something very bad. We people here are about 71 in number and whenever the Independents and some chit, the reply is in the negative. I do not understand what is the reason. We have been also elected in the same way in which the Prime Minister has been elected, yourself have been elected and every other Member of this hon. House has been elected. Anyway, this is my grievance. But I thought this is the time when I could bring it to your kind notice.

Now, I come to the Bill. There are three most important points on which I would like to speak, and to which I would like the attention of the hon. Minister to be drawn. According to me, there should be uniformity in sales tax throughout the country. The second point is, a high powered Commission should be appointed by the Government, to have a thorough

study of the sales tax structure in the various States. The third point is—it is very, very important—that as we all know, it is an accepted law that taxing statutes should be prospective and never retrospective. And so, clause 9 of this Bill which the hon. Minister is bringing here, should not have been given retrospective effect.

As we all know, this Bill has been brought before this hon. House so as to cover up certain legislative defects which were existing in the principal Act of 1956. The Supreme Court which is the highest judiciary of our country has pointed out in some cases, particularly in the Yadalam case, that no central sales tax should be levied if there is no provision to levy sales tax under the State laws.

On the second of this month, the Supreme Court has given another judgment to the same effect. I am sure that the hon. Minister knows it very well that on the second of August, when the Supreme Court has given a judgment, the Government has come forward to bring a law against the judgment of the Supreme Court which is the highest judiciary in our country.

The levy of central sales tax varied from three to 10 per cent depending upon the nature of the transaction. In this respect, a serious problem arose, and that problem is that the dealers who had not collected the sales tax from the parties but who have been assessed and paid sales tax on the levy made on them by the sales tax authorities claimed refund. This demand of the sales tax was wrong and unjustified, particularly when the taxing statutes should be prospective, as I said just now, and not retrospective in nature. The matter is substantive and creates a liability, and therefore, it should not take place.

Here, I would say one thing. I do not dispute the right of Parliament to legislate on any subject under the Constitution. This type of legislation, after repeated verdicts of the Supreme Court against the Government action, is wrong. We should give proper respect to the judiciary.

Coming to the present Bill, I would say that for the purpose of validation of levy

which was illegal according to the Supreme Court, the Government issued an ordinance on the 9th June, 1969. As I stated earlier, this Bill is before this hon. House with a view to replacing the said ordinance. I would like to draw the attention of the House particularly to clause 9 of the Bill in which it has been made retrospective, and I strongly and categorically object to this and all these levies assessed or reassessed and the levy so collected has been made legal under this law with the result that the dealers who have paid the tax have not been given the right to claim any refund whatsoever.

Bringing in such a Bill and making it a law is against the spirit of the Constitution and against the fundamental rights of the individual. It is an encroachment by the ruling party on the fundamental rights of the people and now the Government has come to this House to get this legislation rubberstamped by the House. To me, it is an anti-people legislation. Taxing statutes, as I said already, is always prospective and not retrospective in nature, when particularly it is substantive and not procedural.

Here, I would like to draw the attention of the hon. Minister and of this hon. House to John Mathai's report. John Mathai's report has suggested as back as in 1955 that on account of its yield and flexibility, sales tax has come to occupy a large and indispensable place in the State financial systems. Centralisation of the tax, the Committee has recommended, must be ruled out. The difficulties which confront the tax administrations vary considerably in character and composition from State to State and taken together present a large and almost bewildering variety of problems. It would be hardly possible for the legislative and rule-making power located in the Central Government to deal effectively and promptly with these. It is given on page 519.

In the end, I would like to make a very small submission that Delhi is a distributing centre for Rajasthan, Uttar Pradesh, Haryana and Punjab but there is heavy sales taxation in Delhi as a result of which trade suffers here. It is my submission that the rates of tax in Delhi should be reduced in

order to facilitate the adjoining traders to trade here. That is why I have suggested that there should be uniformity in rate structure throughout the country.

श्री अब्दुल गनी डार (गुडगांव) : चेयरमैन साहब, एक जमाना हुआ, जब सर सिकन्दर हयात खां की मिनिस्टरी पंजाब में थी, उस वक्त वह सबसे पहले 4 आने सैकड़ा सेल्ज टैक्स लगाने के लिए बिल लाये थे और उसका कांग्रेस-वालों ने हाई कमाण्ड की मंजूरी से काला बिल करार देकर विरोध किया, इसके खिलाफ एजी-टेशन किया। श्री बिहारी लाल चानना और शन्नो देवी इसके लीडर थे और बहुत से लोग इसके लिए जेल गये। मैं जानता हूँ कि हमारे बहुत से सीनियर मेम्बर यह कहेंगे कि जमाना बदलता रहता है, उस वक्त यही मुनासिब था कि उसको काला बिल कहा जाय और अब यह मुनासिब है कि जितनी ज्यादा चमड़ी गरीब की उधेड़ी जा सके, उधेड़ लो। चूँकि इसका सबसे ज्यादा असर कन्ज्यूमर पर पड़ता है और आज इस देश में 80 परसेंट कन्ज्यूमर गरीब है, इसलिए इसका सारा बोझा उसी पर जाता है—इसलिए मैं इस बिल को बहुत अहम समझता हूँ।

मैं अपने मिनिस्टर साहब को आपके जरिये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि न सिर्फ यही हुआ कि सेल्ज टैक्स 4 आने से बढ़ कर कहीं पर 8 परसेंट हो गया है, कहीं 10 परसेंट हो गया है, लेकिन इसके साथ ही सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स 3 परसेंट का और ज्यादा लगा दिया गया—इस तरह से कन्ज्यूमर पर एक बहुत भारी दिक्कत और मुसीबत आई। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल भेजने पर टैक्स लगता है—चाहे वह थोड़ा लगता है, लेकिन लगता है, दिल्ली में 1 परसेंट लगता है लेकिन दूसरी स्टेटों 3 परसेंट लगता है। मैंने इसके बारे में दो संशोधन दिये हैं—एक तो यह कि इसको मर्क्युलेट करें ताकि इसके बारे में पब्लिक की राय जानी जा सके और दूसरी यह कि इसको ज्वाइंट

[श्री अब्दुलगनी डार]

सिलैक्ट कमेटी के सुपुर्द करें ताकि वह उस पर विचार कर सके—आया यह मुमकिन है कि सेल्ज टैक्स इन्कम टैक्स की तरह एक ही जगह पर लगे, बार-बार न लगे और उसके बटवारे के लिए राज्यों के साथ तय कर लें कि कितने परसेंट उनको दिया जायगा और कितने परसेंट सेन्ट्रल गवर्नमेंट खुद रखेगी।

दिवकत यह है, चेयरमैन साहब, हर शस्त्र पढ़ा-लिखा नहीं है। हमारे यहां एजुकेशन की तादाद पहले तो 8 परसेंट ही थी, फिर 10 परसेंट हुई, 20 परसेंट हुई, 30 परसेंट हुई, लेकिन अभी भी आधे के करीब लोग ऐसे हैं जो हिसाब किताब से बिल्कुल नावाकिफ हैं, वे लोग हिसाब किताब नहीं रख सकते हैं। इसका नतीजा क्या होता है, वे बहियां लेकर सारा दिन इन्स्पेक्टर के यहां खड़े रहते हैं, उसकी जवाब-देही करते रहते हैं, कभी मर्जी आई मालिक की, बुला लिया, न मर्जी आई, नहीं बुलाया। अगर एक ही स्टेज पर, इनीशियल स्टेज पर टैक्स लग जाय, जितना भी टैक्स ग्राप लगाना चाहें लगा-इये, उसमें कमी न कीजिए, इस तरह से उसमें इवेजिन की गुंजाइश नहीं रहेगी। इस तरह से हर एक को चीज एक ही दाम पर मिलेगी और आपको पूरा रेवेन्यू भी मिल जायगा।

अगर इनको मेरी दोनों तजवीजें मंजूर न हों तो फिर मैं यह अर्ज करूंगा कि आप इस पर विचार करें कि यह एक ही जगह ले लिया जाय और जितना मुनासिब समझे स्टेटों के साथ बांट लें। इसके दो फायदे होंगे—एक तो यह कि जितना आज स्टेट और सेंटर को सेल्ज टैक्स मिलता है उससे डबल आमदनी इनकी हो जायगी—सेंटर को भी डबल आयेगा और स्टेट को भी डबल आयेगा, क्योंकि उसमें किसी को इवेजिन का मौका नहीं मिलेगा। आम तौर पर

ऐसा होता है कि दो तरह की ट्रांजेक्शन चलती हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है—बड़े-बड़े घाघ बंटे हैं जो पहले ही अण्डर-इन्वाइसिंग कराते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि जितना माल बाहर से आता है उससे कितने गुना ज्यादा माल उसी कीमत पर चला जाता है। उसके बाद ग्रावर-इन्वाइसिंग होता है, बड़े-बड़े आफिसर्ज और दूसरे लोग, चाहे पब्लिक सैक्टर के हों या प्राइवेट सैक्टर के हों, इससे फारेन-एक्सचेंज बाहर के मुल्कों में जमा हो जाता है, पहले से तय हो जाता है कि इतना जमा कराना है। यही हालत सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स और लोकल सेल्ज टैक्स की है। लोग दो तरह से माल बेचते हैं—नं० 1 का माल जो ईमानदारी के साथ बेचा जाता है, बाकायदा पर्चा कटता है, दर्ज होता है, बम्बई से चला और दिल्ली पहुंचा और दिल्ली से चला पंजाब पहुंचा। दूसरा नं० 2—इसमें पर्चा नहीं कटता, नकद पैसा दो और माल उठाओ, हम जानें हमारा काम और इनके पास इतनी मशीनरी नहीं है कि ये उसकी जांच कर सकें कि कितना माल इन्होंने कहां से लिया और कहां निकाला। मेरी हाथ जोड़ कर यह अर्ज है कि इसके दो फायदे होंगे—हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा दूसरे—हमारा मौरल—आज हर जगह पर हम जलील हो रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग की रोज चर्चा होती है, बद-दयानती की चर्चा होती है, उसकी सुविधा इस तरीके में नहीं रहेगी।

अगर मेरा यह सुभाव आपको मंजूर हो तो वेशक आप अपनी मर्जी की सिलैक्ट कमेटी बना लें और इस बिल को उसके हवाले कर दें या खुद ही अपने बिल में इस किस्स की तरमीम कर लें। चेयरमैन साहब, मैंने इस बिल को पढ़ा है, काभी मायूस-कुन बिल है, इसमें कोई तरक्की दिखाई नहीं देती, बल्कि उलझनें दिखाई देती हैं। इसीलिये मैंने अर्ज किया है कि इसको सर्कुलेट करो या सिलैक्ट कमेटी के सुपुर्द करो। अगर कुछ नहीं करना चाहते तो काला-बिल कहने वाले मेरे दोस्तों—उस वक्त कांग्रेस का

ہنڈا جین کے ہاٹھ میں تھا، ان میں سے میں بھی ایک تھا، میں اس وقت آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا सदस्य تھا اور اپنے جیل کے پریزیڈنٹ تھا، ہم نے اس وقت ہائی کمانڈ کے حکم سے ہنڈا بٹایا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے انتخابات میں یونینسٹ جین کی تادیب 114 تھی، صرف 13 رہ گئے، اسی طرح سے خود ن کر کے، 18 تاریخ کے بعد، میں پریزیڈنٹسٹ انڈیکشن کا جیک نہیں کر رہا ہوں، لیکن 18 تا 10 کے بعد پتا نہیں کہ میں نے اپوزیشن والے آفیشیال پارٹی میں چلے جاؤں گے اور کتنے آفیشیال پارٹی والے بھر جائیں گے۔ اب حال اس وقت تو سنڈل سولج ٹیکس کی بات ہے، اس کو ایک جگہ پر لو، پورا لو، جس سے آپ کو کمی نہ پڑے، اپنا بھر پورا کر لو اور اس میں سٹیم کو دو۔

[شری علی گنی ڈار (گورنمنٹ) چیرمین صاحب] ایک دن ہوا جب سر سکندر حیات خان کی مشنری پنجاب میں تھی۔ اس وقت سب سے پہلے 2 آئے تھے۔ سیز ٹیکس لگانے کے بل لائے تھے۔ اور اس کا اکثریت والوں نے مل کر کمانڈ کی منظوری سے کالابلی قرار دیکر لہر دیا۔ اس کے خلاف ایکٹیشن کیا۔ شری ہمارے لیل چنانہ اور شندولوی اس کے بڑے تھے اور بہت سے لوگ اس کے لئے جیل گئے۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے بہت سے سیز ممبر ہیں کہ زمانہ بدلتا رہتا ہے اس وقت بھی مناسب تھا کہ اس کو کالابلی کہا جائے اور اب یہ مناسب ہے کہ جتنی زیادہ چٹری غریب کی اور لوگوں کے اور بھڑو۔ چونکہ اس سے زیادہ اثر کنزرویٹو پر پڑتا ہے اور آج اس ویش میں 80 پریسٹ سنٹیور غریب ہے اس لئے اس کا سارا بوجھ اس پر جاتا ہے۔ اس لئے میں اس بل کو بہت اہم سمجھتا ہوں۔ میں اپنے مشنر صاحب کو آپ کے ذریعے رکوئسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف یہ ہوا کہ سیز ٹیکس 2 لگنے سے بڑھ کر کہیں پر 80 پریسٹ ہو گیا ہے۔ کہیں 100 پریسٹ

ہو گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی سیز ٹیکس میں 30 پریسٹ اور زیادہ لگا دیا گیا۔ اس طرح کے کنزرویٹو پر ایک بہت بھاری دہشت اور بھاری دہشت آئی۔ ایک ٹیکس سے دوسری ٹیکس میں مال بھیجے نہیں لگتا ہے۔ چاہے وہ غنڈا لگتا ہے۔ لیکن لگتا ہے۔ دہشت میں ایک پریسٹ لگتا ہے لیکن دوسری ٹیکسوں میں 30 پریسٹ لگتا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں دو سنڈولوں دئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو کورکریٹ کریں تاکہ اس کے بارے میں چیک کی رائے جانی جائے اور دوسری یہ کہ اس کو جو انٹرنیشنل ٹیکس کمیٹی کے سپرد کریں تاکہ وہ اس پر چار کر کے آیا۔ غرض کہ سیز ٹیکس کو ایک ٹیکس کی طرح ایک ہی ٹیکس پر لگایا جانتے۔ بار بار نہ لگے اور اس کے ثواب کے لئے راجیوں کیساتھ ملے کر کریں۔ کہتے پریسٹ ان کو دیا جائیگا اور کہتے پریسٹ سیز ٹیکس کو غور دیکھیں گے۔

دقت یہ ہے۔ چیرمین صاحب۔ ہر شخص پر ٹیکس لگایا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک کوشش کی تعداد پہلے تو 8 پریسٹ تھی۔ پھر 10 پریسٹ ہوئی۔ 20 پریسٹ ہوئی۔ 30 پریسٹ ہوئی۔ لیکن ابھی آدھے کے قریب لوگ ایسے ہیں جو حساب کتاب سے بالکل ناواقف ہیں۔ وہ لوگ حساب کتاب نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بیان لے کر سارا دن ٹیکس کے یہاں کھڑے رہتے ہیں۔ اس کی خواہش یہ کرتے ہیں کہ میں بھی وہی آئی ٹیکس کی تو بلا لیا۔ نہ صرف آئی ٹیکس نہیں بلایا۔ اگر ایک ہی شیج پرائیویٹ شیج پر ٹیکس لگ جائے جتنا بھی ٹیکس لپ لگانا چاہیں لگائیں۔ اس میں کمی نہ کیجیے۔ اس طرح سے اس میں ایڈیشن کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس طرح سے ہر ایک کو ایک چیز ایک ہی دام پر بیچی اور آپ کو پورا ریونیو بھی مل جائیگا۔

اگر ان کو میری دونوں تجویزیں منظور نہ ہوں تو پھر میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اس پر دچکر میں کر یہ ایک ہی جگہ لے لیا جائے اور جتنا مناسب سمجھیں سٹیٹوں کے ساتھ بانٹ لیں۔ اس کے دو فائدے ہونگے ایک تو یہ کہ جتنا آج سٹیٹ اور سینٹر کو ملنے لگے اس سے ڈبل آمدنی ان کی ہو جائیگی۔ سینٹر کو بھی ڈبل آئیگا اور سٹیٹ کو بھی ڈبل آئے گا کیونکہ اس میں کسی کو بھی ایوزن کا موقع نہیں ملے گا عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دو طرح کی ٹرانزیکشنز چلتی ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے۔ بڑے بڑے گھاگ گھٹے ہیں جو پہلے ہی انڈر انوائسنگ کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا مال باہر سے آتا ہے اس سے کتنا زیادہ مال اس قیمت پر چلا جاتا ہے اس کا بعد اور انوائسنگ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے افسر زادہ دوسروں کے بینک سیکرٹس ہوں یا پرائیویٹ سیکرٹس ہوں ایسا کرتے ہیں اور اس سے فارن ایکسچج باہر کے ملکوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ پہلے طے ہو جاتا ہے کہ اتنا ایکسچج کرنا ہے۔ یہی حالت سینٹر سلیٹیکس اور لوکل سلیٹیکس کی ہے۔ لوگ دو طرح سے مال بیچتے ہیں نمبر اکہ مال جو ایمانڈری کیساتھ بیچا جاتا ہے۔ بانائدہ پر چلا ٹاٹا ہے۔ درج ہوتا ہے۔ بسٹی سے چلا اور دہلی چمچا اور دہلی سے چلا اور پنجاب پنپا۔ دوسرا نمبر ۲۔ اس میں پرچہ نہیں کٹتا۔ تقریباً دو اور مال اٹھاؤ۔ ہم جائیں اور ہمارا کام ان کے پاس اتنی شینری ہے کہ یہ اس کی حاجت نہیں کہ کتنا مال انھوں نے کہاں سے لیا اور کہاں نکالا میری لگتہ جو ٹرک یہ عرض ہے کہ اس کے دو فائدے ہونگے۔ ہمارا ریونیو بڑھے گا۔ دوسرے ہمارا مورل آج سر جگہ پر ہم ڈبل ہو رہے ہیں بیک مارکیٹنگ کی روز چرچا ہوتی ہے۔ بددیانتی کی چرچا ہوتی ہے اس کی سوبد ہمارا اس طریقے میں نہیں رہے گی۔

د اگر میرا یہ سوچا تو آپ کو منظور ہو کر ایک آپ اپنی مرضی کی سلیکٹ کیٹی بنائیں۔ اور اس بل کو اس کے حوالے کر دیں یا خود ہی اپنے بل میں اس قسم کی ترمیم کریں۔

ر جسر میں صاحب میں نے اس بل کو ٹرہا ہے کافی مایوسگیں بل ہے۔ اس میں کوئی ترمیمی دیکھی نہیں دیتی بلکہ انجینس دکھاتی دیتی ہیں اس سے میں نے عرض کیا ہے کہ اس کو سر کیٹیٹ کرو یا سلیکٹ کیٹیٹ

کے سپر ڈرو۔ اگر کرکے نہیں کرنا چاہتے تو کالا بل کہتے والے میرے دوستوں اس وقت کانگریس کا جھنڈا جوڑ کے ہا جھڑ میں تھاں میں میں بھی ایک تھا۔ میں اس وقت آل انڈیا کانگریس کیٹیٹ کا صدر تھا اور اپنے ضلع کا پریسیڈنٹ تھا۔ ہم نے اس وقت لمائی کا نڈکے حکم سے قبضہ امٹھایا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے چنانچہ میں پریسیڈنٹ جن کی تعداد ۱۱۲ تھی صرف ۱۳ رہ گئے۔ اس طرح سے خدا نہ کرے ۱۸ تاریخ کے بعد میں پریزیڈنٹیشنل الیکشن کا ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن ۱۸ تاریخ کے بعد چاہیں گے اور ایوزن والے آئینل پارٹی میں چلے جائیں گے اور کتنے آئینل پارٹی والے ادھر جائیں گے بہر حال اس وقت تو سینٹرل سلیٹیکس کی بات ہے اس کو ایک جگہ پر لو۔ پورا لو جس سے آپ کو کمی نہ پڑے۔ اپنا گھر پورا کر لو اور اس میں سے سٹیٹس کو دو۔

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि यह विधेयक जो हमारे सामने है—सेन्ट्रल सेलज टैक्स विधेयक—इससे आम जनता पर बोझा पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि यह विधेयक जो यह सरकार लाई है, कोर्ट के कुछ फैसलों के कारण लाई है, जिन फैसलों से राज्यों के ऊपर असर पड़ने जा रहा है और उसका निराकरण करने के लिए इन्होंने यह विधेयक यहाँ पेश किया है। इसके पास होने से राज्यों को रिफंड करने की ज़रूरत नहीं होगी और 10 साल के दरमिया

जो पैसा उनको मिला है वह उनके पास ही रह जायगा। राज्यों को राहत पहुंचाने के लिए इस बिल को यहां लाये हैं। लेकिन सेल्स टैक्स, जैसा आप जानते हैं मोटे तौर पर, जो और इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं, उनमें से एक है। हम यह भी जानते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेज का बोझ हिन्दुस्तान की आम जनता पड़ता है। आजादी के बाद और योजनाओं के बाद के आंकड़े बताते हैं कि हिन्दुस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेज, चाहे वह सेल्स टैक्स हो या कोई दूसरे टैक्स हों, फाइन हंड्रेड टाइम्स से भी ज्यादा बढ़े हैं। इनके विपरीत, जो डायरेक्ट टैक्सेज हैं जोकि धनी लोगों पर पड़ते हैं वह बहुत कम बढ़े हैं। अगर लग्जरी पर सेल्स टैक्स या किसी तरह का और टैक्स लगाने की बात हो तो उसको हम समझ सकते हैं, लग्जरी पर टैक्स लगने चाहिये, राज्यों को या केन्द्र को वह आमदनी मिलनी चाहिये। लेकिन आम तौर पर जो अप्रत्यक्ष कर हैं, जिसमें सेल्स टैक्स भी आता है, वह आम जनता के खिलाफ है क्योंकि उनका बोझ जनता पर ही पड़ता है।

16 hrs.

हमारे लोको प्रभु जी ने कहा कि इसपे ट्रेड पर धक्का लगेगा। लेकिन अभी ट्रेड किसके हाथ में है? अभी हिन्दुस्तान में ट्रेड मुनाफाखोरों के हाथों में है, प्राफिटीयर्स के हाथों में है। हम मान सकते हैं कि उनको थोड़ा बहुत धक्का लगे लेकिन हकीकत में ये सेल्स टैक्स को देने से भागते हैं चीजों की बिक्री करके बेजा मुनाफा उठाते हैं—चीजों को रोक कर बाजार में कमी पैदा करते हैं और फिर मुनाफाखोरी करते हैं इसलिए जनता को इसके प्रति क्या आकर्षण हो सकता है। ये व्यापारी लोग एडवर्टीजमेंट के जरिए से अपनी बिक्री करते हैं लेकिन जनता के उपयोग की जो चीजें होती हैं उनको सही रूप से एडवर्टीजिंग नहीं करते हैं बल्कि जिन चीजों की जरूरत नहीं होती है, जोकि लग्जरी की

चीजें होती हैं उनको एडवर्टीजिंग करके कंडीशन कर देते हैं, इसका मतलब यह है कि जिससे समाज और आम जनता को फायदा होना चाहिये, उन चीजों के प्रोडक्शन और बिक्री के लिए, विज्ञापन के द्वारा जो व्यापार का सिलसिला होता, है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जिन चीजों से उनको ज्यादा फायदा हो उन्हीं के लिए विज्ञापनों का सिलसिला इस्तेमाल किया जाता है।

सभापति जी, जब इस देश की सारी अर्थ-व्यवस्था नियोजित हो जायेगी, उन दिनों में भी सेल्स टैक्स की थोड़ी जरूरत रहेगी। लेकिन उस वक्त जो सेल्स टैक्स रहेगा वह इसलिए कि उससे जो रिसोर्सेज इकट्ठा हों वह समाज की जरूरतों पर, प्रायर्टी के मुताबिक इस्तेमाल किये जा सकें। जिस चीज की जरूरत जल्द हो उसके लिए, टैक्सेज को थोड़ा बढ़ाकर रिसोर्सेज को मौबिलाइज किया जाये। इस हिसाब से सेल्स टैक्स पूर्ण नियोजित समाज में भी रहेगा।

इसी सन्दर्भ में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सेल्स टैक्स से चाहे राज्यों को फायदा हो या सेंटर को हो लेकिन क्या कभी सरकार ने इस बात पर भी गौर किया है कि जो टैक्स क्लेवर्टर्स हैं वे कितनी ईमानदारी से काम करते हैं? इसी तरह से चाहे सेल्स टैक्स हो या किसी तरह का कोई दूसरा टैक्स, वह जितना आपको मिशन चाहिये उसका वास्तव में कितना हिस्सा आपको मिल पाता है? पिछले सेशन में जब कस्टम की बात आई थी तो मैंने कहा था कि सौ करोड़ की स्मगलिंग होती है। तिबारी कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से सरकार को हर साल इतना पैसा नहीं मिलता है। अफसरों की लारबाही की वजह से, आपको जो चीज मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती है। अफसरों के भ्रष्टाचार, घूसखोरी और नजरन्दाजी की वजह से जो कुछ आपको या राज्यों को मिलना

आहिए वह नहीं मिल पाता है। इसके लिए सरकार क्या कदम उठाती है।

इसके अलावा इसमें बुनियादी बात यह है कि यदि थोड़ी देर के लिए रिसोर्स मोबिलाइज करने के लिए, योजना के दृष्टिकोण से सेल्स टैक्स लगाना लाजिमी हो जाता है तो प्राज की परिस्थिति में जो इंटरनल होल सेल ट्रेड है उसको भी सरकार अपने मातहत ला। सरकार उसको स्टेट और कोअपरेटिव सेक्टर में ले। रिटेल की बिक्री को थोड़ी देर के लिये वैयक्तिक हाथों में छोड़ सकती है लेकिन होलसेल बिक्री को सरकार अपने मातहत ले या कोअपरेटिव के मातहत ले। ऐसा करने से बावजूद इस बात के कि मुनाफाखोरी हो, सेल्स टैक्स का हिसाब-किताब ठीक से न रखा जाये, वे अपना मुनाफा-ज्यादा लगायें और सरकार को उतनी आमदनी न हो, फिर भी बहुत हद तक समाल फायदे में रहेगा।

राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में यहां पर कहा गया कि इसमें ये ये खामियां हैं, ये फायदे हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि समाज को एक नयी दिशा में ले जाने के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम है। जिसको थोड़ा सा भी जान है, जो थोड़ा सा भी वैज्ञानिक ढंग से सोचता है वह इसकी तारीफ करेगा। उसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि सेल्स टैक्स आपको या राज्यों को मिले जितना कि मिलना चाहिये जोकि अभी हकीकत में आपको नहीं मिल रहा है—अफसरों के भ्रष्टाचार के कारण या व्यापारियों के द्वारा दो किताबें रखने के कारण, तो उसके लिए लाजिमी हो जाता है, एक ही रास्ता है कि यह जो इंटरनल होलसेल ट्रेड है उसको सरकार अपने हाथ में ले। थोड़ी देर के लिए अगर सरकार अपने कब्जे में नहीं लेना चाहती है तो फिर कोअपरेटिव के मातहत उसको ले और भ्रष्टाचार को समाप्त करे। यदि ये सब कदम उठाये जाते हैं तो समाज

फायदे में रहेगा, अवाम की हालत में भी बेहतरि आयेगी और हम यह कह सकेंगे कि इन रिसोर्स का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए किया जा रहा है। लेकिन जिस रूप में यह विधेयक लाया गया है, उसके साथ-साथ अगर ये कदम नहीं उठाए जाते हैं तो फिर उससे साफ है कि इसका बोझ हिन्दुस्तान की आम जनता जिसके 75 फीसदी लोग तीन आने रोज पर बसर करते हैं, उन पर पड़ने जा रहा है। समाजवाद की बात जो ये कहते हैं, वह तो दूर रही, धनी और धनी और आम जनता और ज्यादा गरीब होने जा रही है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक की मुखालिफत करता हूँ। मैंने भी संशोधन दिया है कि इसको आम जनता की राय के लिए सर्कुलेट किया जाये। अगर आप इसको सेलेक्ट कमेटी में देते हैं तो वह भी अच्छी चीज है। इसमें यदि आप ये संशोधन करते हैं तो यह बड़े महत्व वाला विधेयक है और अगर नहीं करते हैं तो यह आम जनता के खिलाफ, उनकी बेहतरी के खिलाफ, उनके विकास के खिलाफ और उनके भविष्य के खिलाफ होगा। मोटे तौर पर मैं इस विधेयक की मुखालिफत करता हूँ।

SHRI M. MEGHACHANDRA (Inner Manipur) : We are just now discussing the Central Sales-tax (Amendment) Bill, 1969. Which seeks to amend the Central Sales Tax Act, 1956. This particular Bill has been brought to replace the Central Sales Tax Amendment Ordinance which has Issued, as the House is aware, in the month of June, 1969. In this connection, I want to point out a few things.

I still do not understand how this Ordinance was brought at this hour. There has been a reference in the 'Statement of Objects and Reasons' given in the Bill that the issue of this Ordinance had been made necessary because of the Supreme Court's judgment in the well-known Yaddalam case. In the Yaddalam case the judgment was pronounced in 1964 in the month of November. So, some 4 years and 6 months had passed and

[Shri M. Meghachandra]

only in the month of June, 1969 this particular Ordinance was brought, and in order to replace that Ordinance, this Bill has been brought before the House. This Bill has only 11 clauses but these 11 clauses will have very grave and far reaching consequences because this Bill, strictly speaking, is not prospective. This Bill will have retrospective effect-retrospective effect not from the day when the judgment was given but from the day when the Act came into force. This Act will have effect for more 10 years and during the course of these 10 years this sales tax will have to be imposed and from many dealers this sales tax will be collected. This levy of sales tax from dealers from all States and Union Territories with retrospective effect should not be supported, and in this connection I humbly submit that this House has the power or authority to pass such a law, but we also have to look towards the element of hardship the people and the dealers have to suffer if this Bill is given retrospective effect. As I have submitted, if this Bill is passed, it will have far-reaching consequences. What the Supreme Court pointed out in 1964 that will be overcome. But I submit that it is good that we should have a comprehensive Central Sales Tax law. But, then if we go or with this particular Bill and make it retrospective, the element of hardship should also be taken into account. Already many State Governments have to recall tax amounts which have been refunded. Then there are still more taxes to be levied and collected. All these things are there and, therefore, I will suggest that something is done so that the Bill is so amended that the retrospective element is taken out. This Bill in the few clauses also introduces some other matters. Reference may be made to the imposition of the tax in States where there is no local sales tax law. Then again it will be imposed not only in the sale of commodities in one State but this will be imposed in the subsequent sales and, therefore, this becomes multi-point tax.

Then again, in this Bill, there is what is called validation of the actions of the Government in the matter of assessment, in the matter of collection and levy made in the past. There is

one provision safeguarding the interests of those who *bona-fide*, relying on the judgment of the Supreme Court, did not collect this tax. But my submission in when the Bill is given retrospective effect for more than 10-12 years, then it will cause much hardship to the dealers and the people from whom this tax is collected.

श्री हनुम चन्द कछवाय (उज्जैन) : सभा-पति महोदय, जो बिल हमारे सामने है यह देखने में ऐसा लगता है कि सारा भार इसका बहुत छोटे-छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा। इसमें एक बात कही गई है कि पिछले 12 साल का भी लिया जायगा। आखिर अभी तक लिया क्यों नहीं ? मैं इसके दो, चार मुद्दे मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ। यह जो कर एकत्रित करने वाले इंस्पेक्टर है ये कितनी अधिक तादाद में भ्रष्ट हो गये हैं इसको हम सभी जानते हैं। यदि किमी दूकानदार को आज बिक्री कर भरना है, इंस्पेक्टर की जब में 50 रु० डाल दीजिए तो डेढ़, दो साल की छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार के अनेकों केसेज हमारे सामने हैं। आप और बढ़ाने जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि जिस चीज का उत्पादन जहां से होता है सारा कर वहां ही लगाया जाय। बहुत से छोटे-छोटे व्यापारी जो 50 रु० 200, 400 रु० की दुकान करते हैं उन्हें ही हैरान किया जाता है। वे सब प्रकार का हिसाब-किताब नहीं रख सकते। पान, बीड़ी की दुकान करने वाला व्यक्ति जो 5, 10 रु० की बीड़ी लाकर बेचता है आज उसमें कहा जाता है कि तुम बिक्री कर चुकाओ, जिसके पास कोई हिसाब नहीं है, जो मुदिकल से अपनी गुजर करता है, तो वह कैसे आपको बिक्री कर दे सकता है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि आप लोगों को राहत दीजिये, खास कर छोटे दुकानदारों को राहत सरकार दे। आप देखें कि सरकार जितने अधिक कानून बनाती है व्यापारी उतना

[श्री हुकमचन्द कछवाय]

ही अधिक चतुर होता जाता है। कुछ चतुर लोग हैं, बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने अपने कारखानों के अन्दर कुछ वकील लोग इस बात के लिए रखे हैं कि सरकार जो कानून बनाये उस से किस प्रकार बचा जाय, इसी बात की खोज में वे लोग लगे रहते हैं और उन्हें बहुत बड़ी तनख्वाह दी जाती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि एक व्यक्ति को कष्ट हो वह ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि हजारों व्यक्तियों को कष्ट हो।

कपड़े का उद्योग है। आप को जितना टैक्स लगाना है कपड़े के दूकानदार पर लगाये। जब गेट से कपड़ा बाहर निकले उस समय सारे टैक्स लगा लीजिये। लेकिन मार्केट में आने के बाद जो एक, दो गज कपड़ा बेचता है उस पर बिक्री कर लगाया जाय इससे उसको काभी दिक्कतें आती हैं, और जब मर्जी आती है इन्स्पेक्टर पहुंच जाता है और कहता है कि अपना हिसाब बताइये। लेकिन कुछ चतुर लोग हैं जो दो प्रकार के रजिस्टर रखते हैं। कुछ तो बिल देकर कपड़ा बेचते हैं और कुछ इस प्रकार के व्यापारी हैं जो बिल देते नहीं हैं। तू मेरी मत कह, मैं तेरी न कहूँ, चुप ले जा, हिसाब कर जा। इस प्रकार का भी लोग व्यापार करते हैं। शायद मंत्री महोदय जानते हैं, काफी दूकानदारों से उसका सम्बन्ध है और वह परिचित हैं कि कौन किस प्रकार का है। वह जानते हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि यह जो पिछले 12 साल का लेने की बात कर रहे हैं इसमें दिक्कतें आयेंगी। आप इस बात की खोज कीजिए कि क्यों इन्स्पेक्टर ने उनको छोड़ा है कुन लेकर। मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि दूकानदारों से बड़ी मात्रा में लोग पैसा लेते हैं और इन्स्पेक्टर ऐसे दूकानदारों को छोड़ देते हैं। तो जिन दूकानदारों ने इन्स्पेक्टरों के कारण पैसा नहीं भरा उसके लिए व्यापारी

दोषी नहीं हैं, बल्कि वे इन्स्पेक्टर हैं उनकी जांच कीजिए और उन दोषी अधिकारियों को सजा दीजिए। इस प्रकार केसेज को बारीकी से देखना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जायगा तो सरकार को जो कर मिलना चाहिये था वह नहीं मिलेगा परिणाम यह होगा कि सरकार और टैक्स बढ़ायेगी, बिक्री कर और आयकर बढ़ायेगी जिसका असर साधारण जनता पर पड़ेगा और जनता परेशान होगी। आप हर चीज का रेट तय कर दीजिए कि कितन-कितन चीजों का क्या दाम होगा जिससे ठीक दाम पर लोगों को जो चीज मिले और दूकानदार मन माफिक रेट न लगायें। इस श्रोर उचित ध्यान दिया जाय। आशा है मंत्री जी इस पर अवश्य ध्यान देंगे।

श्री नाथूराम अहिरवार (टीकमगढ़) : सभापति महोदय, जो मेन्स टैक्स (संशोधन) विधेयक पेश किया गया है, उसके सम्बन्ध में मैं अपने कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय उन पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे।

इस बिल का स्कोप बहुत लिमिटेड है। इस में कहा गया है कि जो डीलर इंटर-स्टेट ट्रेड करेंगे उनसे सेल्स टैक्स वसूल किया जायेगा। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। दिल्ली का एक डीलर हरियाणा में जाकर या गाजियाबाद में जाकर उत्तर प्रदेश के एक डीलर को माल देता है। तो सरकार उम डीलर से टैक्स वसूल करेगी या इससे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बड़े-बड़े कस्बों में हैं और वहां पर डीलर बन गए हैं। इसलिए इस बिल में एक ऐसा क्लॉज भी होना चाहिये कि डीलर कौन है।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह से टैक्स पर टैक्स लगाने से कैसे काम चलेगा। कई लोगों के हाथों में माल जायेगा। बजाय इसके हर जगह पर सेल्स टैक्स लगे बेहतर होगा कि उत्पादन की जगह पर एक बार

टैक्स लगा दिया जाये और दूसरे लोग परेशानी न उठाये। ऐसा न करने पर आप को भी एक बहुत बड़ी फौज तैयार करनी पड़ेगी इन्स्पेक्टरों की सेल्स टैक्स आफिसरों की और कमिश्नरों की तथा उनका गोरखधन्धा लम्बा चलेगा।

मैं देखता हूँ कि हमारे एरिया में तम्बाकू होती है। आपके एक्साइज इन्स्पेक्टर वहाँ जाते हैं। मान लीजिए कि एक एकड़ में 100 मन तम्बाकू हुई। अगर उन लोगों की जेब में 25 रु० डाल दिये गए तो वह 100 मन के बजाय 25 मन दिखला देंगे और 75 मन पर तम्बाकू वाले को छूट मिल जायेगी। आप एक एक मन पर 100 रु० एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं। अगर किसी किसान को चार-पाँच हजार रुपये का फायदा होता है तो वह 200 रु० आसानी से दे देगा। इस तरह से जितने भी आपके सेल्स टैक्स के आदमी हैं उनका हर बड़े दूकानदार से महीना बंधा हुआ है। वह वहाँ जाकर चाय पीते हैं और जय राम जी की कह कर चले आते हैं। लेकिन प्रश्न तो छोटे दूकानदारों का है, जो ठेले वाले हैं या एक आध हजार की छोटी दूकान वाले हैं, जो बिना पढ़े लिखे हैं, अपना हिसाब नहीं रखते हैं कि कितना माल बिका या कितना उधार गया। वहाँ इन्स्पेक्टर लोग पहुँच जाते हैं तब उन लोगों को इन्स्पेक्टरों के हाथ पर जोड़ने पड़ते हैं। उनको परेशान करने के लिए वह लोग उन की पेशियां लगा देते हैं। उन लोगों के ऊपर मान लीजिए कि 50 रु० जुर्माना होता है तो वह 50 रु० जुर्माने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन 25 पेशियां नहीं चाहते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देकर निर्देश देना चाहिये कि जहाँ पर भी सेल्स टैक्स वसूल किया जाये वह उत्पादन पर ही लगा दिया जाये। जिस तरह से साहूकार को ब्याज पर ब्याज देने पर जिस चीज का दाम 2 रु० है उस का दाम देहात में पहुँचते पहुँचते चार, पाँच रुपया यहाँ तक कि दस रुपये तक हो जाता है, उसी तरह से सेल्स टैक्स के कारण चीजों के दाम जगह-जगह बढ़ जाते हैं।

दुकानदार भी ऐसे चालाक हो गये हैं कि उनकी चोरी कोई नहीं पकड़ पाता है। व्यापारी लोग बहुत होशियार होते हैं। जिस दिन कानून बनता है उससे बचने का तरीका वह ढूँढ लेते हैं। एक दिन मैं बाजार में बैठा हुआ था। एक साहब बोले कि इस दूकानदार की बिक्री रोजाना 1,000 रु० की है लेकिन यह दो तरह के हिसाब रखता है। यह नम्बर दो का व्यापारी है, नंबर 2 का व्यापारी कौन होता है जो अपनी एक हजार की बिक्री पर 200 रु० पर तो सरकार को टैक्स देता है और 800 रु० पर बचा जाता है। 800 रु० का हिसाब उसका प्राइवेट खातों में चला जाता है। जिस प्रकार से डाकुओं और बेईमानों में नं० 8 और नं० 10 के होते हैं उसी प्रकार से व्यापारी भी नं० 1 और नं० 2 के होते हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये।

मैं यही विनती करूँगा कि जो भी टैक्स लगायें वह किसी भी एक स्थान पर लगायें ताकि आप को इतनी बड़ी फौज तैयार न करनी पड़े और व्यापारी भी सरकार को धोखा न दे सकें, साथ ही उपभोक्ता को भी बिना ज्यादा पैसा दिये हुए चीजें सस्ती मिलें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विषयक का समर्थन करता हूँ।

SHRI DATTATRAYA KUNTE (Kolaba): It is very surprising that a Government which calls itself democratic Government and says it wants to function according to the Constitution every now and then comes to this House to legalise Ordinances which lay aside all the judgments handed down by the Supreme Court. This is disrespect of the law and disrespect of the Constitution. It has become the practice for this Government to issue such Ordinances. In this particular case, the first decision came in 1964; later in 1963 a number of decisions were given. All the same during the whole of the Budget session of this year the Government did not care to bring any law before this House. But within three weeks after the House had

[Shri Dattaraya Kunte]

adjourned, it made the President given an Ordinance and it is really surprising that the powers of the President should be so misused by this Government, which swears by Democracy but wants to legalise but has been decided as illegal by the Supreme Court. If it had been decided as illegal by the Supreme Court, what would have happened? At the most, so much of money would have been forced to be paid out of the Consolidated Fund which was illegally collected. Is it laid down in the Constitution that an ordinance should be issued to do such infamous things? First of all, the draftsmen had committed a mistake, and the Minister who brought the Bill before the House committed a mistake, and the House committed a mistake. Why should the poorer tax-payer be penalised for that? We are being asked to say, "All right; validate this." One really does not understand it. I remember the first time, after I came here in 1967, the House validated by an ordinance what the Supreme Court had laid down saying that the working of the Land Acquisition Act was wrong. Now, is there any principle involved involved in bringing this Bill before the House except to say that certain monies which this Government by its own authority or through its own agencies or through other agencies had collected were illegally and wrongly collected? It ought to have been other way round. The State Governments should have said, "We are sorry for it; we have collected monies, and we are refunding it." Or, "If we have not collected it, we will not collect it." Instead of doing that, what has been done?

This is not the first time. Every now and then we find that the Government takes recourse to an ordinance first. It has not the courage, it has not the goodness, it has not the sense of justice to come before the House and openly say, "We have committed a mistake; we request the House to rectify it." What is being told is, an ordinance has been passed and we have to validate it. That way, an Act is being passed. It is a very shameful thing to do, to say the least. It is time that the Government stopped these methods. Otherwise, let them take a big lock and key, go

and lock the Supreme Court, and throw the key into the sea, so that nobody will ever get into the Supreme Court and nobody will dare go to the Supreme Court. What happened to those people who went to the Supreme Court and got this decision? It has only been a Pyrrhic victory.

Did the framers of the Constitution frame the Constitution with a view to allow this authority to issue such ordinances in this particular manner? Not in the least. This law was first passed in 1957, and amended in the year 1958. For all these 10 to 11 years, this Government and this Ministry or Department and those who have been collecting the taxes, have been sleeping, and now, as is said in the Statement of Objects and Reasons a series of decisions came in 1968 from the Supreme Court and there were disagreement between the different high courts. And now, shamelessly, they want to say, "Validate our irregularities, our illegalities, our breach of the law, our breach of the constitution." In this manner, I am afraid it cannot go on for ever. If this House is going to pass this legislation in this manner, because of the brute majority of the party in power, it will be a misuse of democracy.

Therefore, for these reasons—and not for any party reasons—I oppose this measure. I will still earnestly call upon all the honest Members of this House to throw this Bill not because of any policy or any paltry reasons, but by way of telling the Government, "Please, for God's sake, do not put into the treasury this ill-gotten money which you got wrongly from the people."

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI :
Sir, There is no quorum in the House.

MR. CHAIRMAN : The bell is being rung—

Now there is quorum. The hon. Minister may now reply to the debate.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (Shri P. C. Sethi) : Sir, as far as this particular measure is concerned this is a very simple measure. First of all, it is not enhancing the central sales tax which is at the rate of 3 per cent since long. Therefore, if there is any mis-

apprehension with regard to this fact that this Act is going to increase the central sales tax, that is entirely wrong. Secondly, this Bill, as has been apprehended by the hon. Member Shri Himatsingka, is not going to increase the arena. The central sales tax was applicable to all goods which travel from one State to another State since 1953 when the Act came into force. Therefore, this particular Bill which is before the House for consideration is not increasing the arena or the number of goods or articles that were being put under sales tax.

The hon. Member, Shri Yajna Datt Sharma raised this question that the entire tax structure with regard to sales tax has to be examined, whether sales tax has to be on a multiple point basis or on a single point basis or just as in the case of excise duty on sugar and cloth it should be on the basis of tax at the production point. I would only like to say in this connection that the entire matter is before the Fifth Finance Commission. After receiving their report we intend to bring before this House a more comprehensive legislation when we can go into this aspect of the problem, whether a particular type of sales tax has to be imposed in this manner or any other manner.

But I would also like to bring to the notice of this hon. House it has been our experience that the State Governments are generally resenting it. They do not like that the power to levy excise duty should be taken in respect of more goods because that snatches away from the State Governments a considerable part of their revenue. As far as this particular central sales tax is concerned, whatever is levied at the rate of 3 per cent, under article 269 (1) of the Constitution completely accrues to the State Governments. Therefore it is not a case, as has been apprehended by some hon. Members, where we are having centralisation. Shri Birla said that we are having more and more centralisation of taxes. But as far as this particular tax is not a centralised tax, it is entirely collected by the State Governments by central sales tax officers and department and according to this provision of the Constitution it accrues completely to the State Governments and not to the Central Government.

SHRI R. K. BIRLA : Then why is the

Centre unnecessarily taking this burden of collection? If it is a State tax let it be collected by them.

SHRI P. C. SETHI : Goods are transported from one State to another and therefore the State Governments lose. It is possible that in one State one article may be produced in a greater quantity than in another State. Therefore the State Governments would like that whenever goods travel from their States to another State a part of the revenue should go to them. That is why in Parliament we have taken upon ourselves this legislation for the convenience of the States.

16 34 hrs.

[SHRI K. N. TIWARY—in the Chair]

The hon. Member Shri Lobo Prabhu raised one question. When the clauses come up he is also going to move an amendment to the effect that this should not be given retrospective effect of more than three years. If we accept his amendment or his line of argument the thing would be that the entire revenue which has been collected to the tune of Rs. 70 to 75 crores by various State Governments would not be given. Various State Governments are involved and their financial position would be in a very precarious state. For example, there is Rs. 44 crores in the case of Maharashtra, Rs. 14.60 crores in the case of Gujarat, Rs. 5.5 crores in Kerala, Rs. 1.95 crores in Mysore, Rs. 2.55 crores in Madras and Rs. 0.05 crore in Madhya Pradesh. Therefore, all these amounts come to a total of Rs. 70 crores for the various States.

Secondly, supposing we take a decision not to give it retrospective effect. What will happen? Will it go back to the consumers? No, it will not go back to the consumers; it will go to the dealers. Therefore, it will not be correct to say that such a help would have helped the consumers in any manner.

Shri Kunte raised the point that by giving retrospective effect we are trying to rot something which was not our intention

[Shri P. C. Sethi]

to do. This is not the position. As a matter of fact, when we take to legislation.....

SHRI DATTATRAYA KUNTE : I never referred to the intention : I referred to the legislation. He is imputing things to me which I have never said.

SHRI P. C. SETHI : When we legislate, we try to see that no loopholes are there. But in a democracy the normal practice is to leave the interpretation of legislation to the courts. Sometimes it so happens that there is some loophole in what we legislate or there is some difference of opinion about its interpretation. In this particular case, when the matter went before the Supreme Court, there was difference of opinion with regard to Interpretation. As far as this particular Act of 1956 is concerned, the Supreme Court in one case in 1964 held that the term "in the same manner" mentioned in the Act go to show that the manner does not refer to this Act but the manner prescribed by the State Government according to their law. This was a difference of opinion with regard to interpretation. After this particular case, with regard to the computation of the tax it was held by the Supreme Court that it has to be computed not only according to this Act but also with regard to the provisions which are there in the State law. Since the Supreme Court gave the judgment that way and since it was not the intention of the legislation that was introduced here, corrective measures had to be taken to give effect to our intentions and that is what we are trying to do.

The hon. Member, Shri Lobo Prabhu, raised the point whether it is desirable to give retrospective effect to such measures. We have got case after case in the Supreme Court and the High Courts where this has been approved by the judiciary. For example, in the case of J. K. Jute Mills Company Limited this position was cleared. Then there was a very famous sugarcane validation Act and a case between the State of Madhya Pradesh and Jaora Sugar Mills where the position has been clarified.

SHRI LOBO PRABHU : That is a court decision ; not a law. Here you are giving retrospective effect by legislation.

SHRI P. C. SETHI : Retrospective recovery has been approved by courts.

SHRI LOBO PRABHU : That was recovery. This is a law for collection.

SHRI P. C. SETHI : This recovery is made according to the law. We are trying to recover it by giving retrospective effect to the legislation. The hon. Member himself accepts that legally this is the correct position.

Shri Abdul Ghani Dar and Shri Kachwai referred to corruption in the collection of sales tax. This is done entirely by the State Government machinery. If there are any cases of corruption, they should certainly be looked into and the machinery should be streamlined so that unnecessary inconvenience is not caused to the taxpayers. If any concrete cases are brought to our notice, it will be our endeavour to bring them to the notice of the State Governments for taking necessary preventive action.

Then, the hon. Members, Shri Abdul Ghani Dar and Shri Shiv Chandra Jha, desired us that it should be sent for circulation to elicit public opinion. We are not bringing forth any new measure before the House. As far as the Central sales-tax is concerned, it is on the statute book since 1955 and it was further amended in 1958. We are not, therefore, bringing forth any new measure before the House and there is no need for its circulation. Secondly, if we send this Bill for circulation, the result will be that as regards the Ordinance which had been promulgated in June and which has to be replaced by an Act only if the Parliament passes it in this session, we will lose that opportunity with the result that the Ordinance will lapse and, if it lapses the result will be that the State Governments will have to return back about Rs. 70 crores to Rs. 75 crores. Therefore, the very fact that it is on account of the State Governments that we had to bring forth this measure and bring it forth in the form of an Ordinance will be completely nullified. So, it will be difficult for me to accept the suggestion of Shri Shiv Chandra Jha for

sending the Bill for circulation to elicit public opinion.

The hon. Member, Shri Shiv Chandra Jha, also suggested that the trade operation should be changed to the cooperatives. Certainly, it is a most welcome suggestion. But the intention of the Bill is not to channelise or change the trade operation. The intention of the Bill is to clarify the position which had emerged on account of the Supreme Court judgment. If the trade channel is changed and more and more cooperatives spring up in the country, it is certainly welcome and it is for the hon. Member and for all of us to see that wherever cooperatives movement can gather momentum, we should certainly try to help it. But I would like to say that this is entirely outside the purview of this Bill.

Then, the hon. Member, Shri Meghachandra, raised a very valid point and that is what we were doing since 1964 to 1968 and from 1968 to 1969. In the year 1964, when the judgment came, it was held by the Supreme Court and it was also considered by the Madras High Court later on, that it was only upto 1956 as far as the cases based on 1956 Act were concerned and therefore, after the changes made in the 1958 Act, it was thought that it would not be applicable to those cases although the Mysore and the Kerala High Courts said differently. But this was the contention. This matter was further raised in the Supreme Court and the Supreme Court gave its clear verdict in the year 1968 that it also applied to the cases even after the amendment of the Act of 1956 by the Act of 1958. The matter came up before us. All of a sudden, it was not possible for us to bring forth an Ordinance. We had to go to the regional councils for consultation and to the State Governments for their points of view and opinion. After soliciting the opinion of regional councils, after soliciting the opinion of State Governments and, specially, after the S.O.S. came from many States and, lastly, from the State of Kerala and after the hon. lady Minister came from here and met the former Deputy Prime Minister and brought to our notice the precarious position in which the States will be placed if this was not done, considering all these ways and means position of the State Governments

including the States of Madras, Kerala, Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh, it was considered necessary to promulgate an Ordinance and that is why this Ordinance was promulgated and we had to deal with the situation in this manner.

Then, the hon. Member, Shri Ahirwar, mentioned that the tax has to be collected at manufacturing point. I have already stated in the beginning that it is under examination and, after receiving the Fifth Finance Commission's report, we are thinking of bringing forth a legislation on this matter where we can go into the intricacies of what type of tax it should be. That matter will come before the House and the matter will also go to the Select Committee. That will be the most appropriate and convenient time for giving the views which the hon. Members want to put forth with regard to this matter.

I would like to explain that we have taken care in this Bill that wherever dealers have not collected the tax, certainly the onus of proof is on them. Mr. Lobo Prabhu said that why the onus of proof should be on them, if they put forward the proof that they have not collected, certainly, to that extent the provision is being inserted in the Bill that it will not be collected from them.

But if they have collected, they would certainly help us in passing it on to the Government.

This is all that I have to say at this stage.

MR. CHAIRMAN : Mr. Yajna Datt Sharma...He is not here.

I shall now put the Statutory Resolution moved by Shri Yajna Datt Sharma to the vote of the House. The question is :

"This House disapproves of the Central Sales Tax (Amendment) Ordinance, 1969 (Ordinance No. 4 of 1969) promulgated by the Vice-President acting as President on the 9th June, 1969."

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN : I shall now put Amendments 8, 9 and 26, together to the vote of the House.

Amendments Nos. 8, 9 & 26 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :

“That the Bill further to amend the Central Sales Tax Act, 1956, and to provide for certain other matters, be taken into consideration”.

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : Now we take up clause-by-clause consideration.

Mr. Dinkar Desai ...He is not here.

The question is ;

“That Clause 2 stand part of the Bill”

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3—(Amendment of section 6)

MR. CHAIRMAN : Mr. Dinkar Desai .. He is not Present.

Mr. N. Shivappa is also not present.

Mr. Lobo Prabhu.

SHRI LOBO PRABHU : I beg to move :

Page 2, line 4,—

add at the end —

“and provided the tax demand is within the period of limitation or three years, whichever is earlier.”
(10)

The Minister has met my amendment in advance and I would, therefore, like to clarify the position to him and to the House. The Bill applies retrospectively for all arrears due from 1958. Now in respect of these arrears, the amount which has been paid and which is due to be refunded by the State Governments, the argument of the Minister is that the amount is a large one, of about Rs. 80 crores or so. If the amount is a large one for the Central or the State Governments, it is certainly a large one for also those who are involved. This is a very simple consideration which the Minister has overlooked. According to

him, the State Governments cannot afford to lose Rs. 80 crores, but the others can afford to pay ! Even granting that, even if we say that there is going to be difficulty and the amount of Rs. 80 crores which has been paid is to be left aside, the question still remains of the other arrears. They fall into two halves : the first upto 1964 ; upto 1964 there was no judicial pronouncement and, therefore, those arrears are in a way less justified than the arrears after 1964, after the Yaddalam case, when there was a judgment that the amount was not due. Now my request to the Minister is a simple one. I am saying, keep your refunds. Let the States, if they like, keep the 80 crores but do not proceed to collect the arrears before 1964 or the arrears after that. The arrears before 1964 may be easy for Government to concede, but if they are recovered, the parties concerned will be put to a very difficult position. Does any one keep books of 10 or 12 years in anticipation that they would be called into account ? Has the Government considered how unfair it is to put a burden on a party to prove that the tax has been paid and that the tax is not due ? So I would suggest, please forget the arrears. There are then certain number of cases which are before the courts. I would, in this connection, refer the Minister to Section 9. Under Section 9 in those cases which have decrees, it would be very unfair if not unconstitutional to say that those decrees are invalid. It is an important point because the Act would be cut down if you say that the decrees go because of the subsequent law. Then there are cases which are pending. Now, in respect of those cases, I think it would be possible for Government to come to some settlement. It will be fair to Government to come to some settlement and at least to allow these parties the costs they have incurred.

Thirdly there are cases which may be instituted for refund. I would agree with the Government that they can be proceeded with. It is possible for the Government to accept my suggestion that arrears be restricted, if they must be collected at all, to the last 3 years and that arrears be restricted to amounts which are not subject to litigation. I think it is such a fair proposition that Government which gets Rs. 80 crores can easily consider forgoing a small amount which may be a matter of

one or two crores. As I say, the Minister must understand the implications of the different clauses of arrears which have arisen and if he foregoes the arrears, I think those who have paid can be asked to forgo 80 crores which the Government is holding against the law as it was then and against the rights of the people not to pay taxes retrospectively.

SHRI DATTATRAYA KUNTE : I would not have liked to say anything, but while justifying the introduction and consideration of this Bill, the hon Minister was pleased to say that only because money will have to be refunded and, therefore, taking compassion on those States who will have to refund the money, he is trying to penalise the public. If he really wants to take compassion on the States, let him give more money from the Consolidated Fund of the Government of India. That is No. 1. No. 2 is : why the States are opposed to this tax at one point ? It is only because the Centre is trying to corner more money. If you are prepared to give more money to the States, let him collect it and give it to the States. The argument advanced is quite funny. The argument is quite legal, it is quite constitutional but it is very funny. What does he say ? He says that the courts have never said that the retrospective application of an Act could be illegal. This is the constitutional position. What have the courts done ? The Courts do not question the legislative competence of this House. The courts are not called upon to say anything about the legislative propriety of this House. The very fact that we are considering this legislation means that if we pass this legislation, the hands of the courts will be bound down. Do we want to bind the hands of justice only because we have the competence or do we want to look into the propriety of it ? Then an hon Member pointed out that till the year 1964 the position of law was not clear and now the position has been clear and if any collections have been made, it would be wrong.

Another point the Minister was trying to make is that there are two interpretations. Unfortunately, the Constitution says that it is only the Courts that will interpret the law and the Constitution.

Whatever may be the submissions of a lawyer or even of Government, it has no status as far as the validity of the interpretation is concerned. We have to accept the interpretation of the court. There could be umpteen interpretations, but as far as the law of the land is concerned, there is only one interpretation that will prevail and that is the interpretation of the Supreme Court. If the hon. Minister thought that his interpretation was the correct one, he should have convinced the court. If he is not able to do so, he must accept the defeat very gratefully.

Then he made a point about the promulgation of the Ordinance. He did not tell us the dates of the advice received from different States. The judgments were delivered in 1968. He has not said that all this information came only after 16th May when the budget session ended. He has only very conveniently said, 'yes, it took time for the information to come.'

I am really surprised to find that Government try to justify the Ordinance and the legislation to replace it for a paltry sum of Rs. 70 crores when they are collecting Rs. 4,000 crores per annum in addition to other money. I do not know whether they want to stifle the Constitution and the real position of law by saying that 'this is our interpretation of law and therefore, we will collect it.'

SHRI P. C. SETHI : As far as my hon. friend, Shri Lobo Prabhu, is concerned, his amendment tries to limit the retrospective effect of this Bill. He also said in the course of his arguments that it is not possible for the parties to keep accounts for such a long period. I would like to remind him that there is a law of limitation in the States according to which there is a prescribed period within which account books can be reopened. Till that period is over, no party who is a dealer or who maintains account books would do away with them. Hence, account books would be available.

Secondly, under sec. 6, the liability will operate in terms of the State law. Therefore, although we are giving retrospective effect, it will operate according

to the State law of limitation. Therefore, we have provided for whatever is possible or available in the various laws of limitation in the States to apply in this case.

Shri Kunte again raised the question of retrospective effect in regard to the amount of Rs. 70 crores and asked whether the Central Government should not give more to the States in lieu of it. I have made it amply clear that under art 269 (1) of the Constitution, the entire proceeds of this tax go to the State Governments. Therefore, the question of giving more to them does not arise.

SHRI DATTATRAYA KUNTE : I said that in case this law is not passed, the money will have to be refunded by the States—this was the difficulty pointed out by the hon. Minister—and asked why the Central Government could not go to the help of the State Governments and give this amount from the Consolidated Fund. Because a mistake has been committed by Government, or Parliament why penalise the tax payer ?

SHRI P. C. SETHI : I do not understand his argument as to ultimately who is going to profit by this. He wants us to ask the State Governments to give this money to the dealers so that this would be passed on to the consumer. We have already said that if some dealers have not collected from consumers, to that extent they will be exempted. If dealers have collected the money, Government have to collect it from them. But if we refund this money, it would not be passed to the consumers but will go the pockets of the dealers. Therefore, I do not understand for whom Mr. Kunte is holding brief.

17 hrs.

SHRI DATTATRAYA KUNTE : I am holding brief for law and the Constitution.

SHRI P. C. SETHI : As far as law and Constitution are concerned, that position is also clear. The intention of the law was to collect the tax according to the Act. But it was interpreted differently. Many times it happens. We formulate certain laws but when it goes to the court, the interpretation is different. The Supreme Court in their wisdom and according to their judgment felt that the words 'in

the same manner did not apply to this Act but only to the manner which was prescribed in the State law. That is why this difficulty has arisen. This is a legal and constitutional difficulty. Ours is a democratic country and the Parliament enacts laws and the courts interpret them, as in all the democratic countries. This difficulty arises in many social legislation also. So, I am not in a position to accept the amendment moved by Shri Lobo Prabhu.

MR. CHAIRMAN : So, I put amendment No. 10 to the vote of the House.

Amendment No. 10 was put and negatived

MR. CHAIRMAN : The question is :

“That clause 3 stand part of the Bill”.

The motion was adopted

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : There are some amendments to clause 5.

Clause 5—(Insertion new section 8A)

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : I beg to move :

Page 2, line 35,—

for “May, 1966” substitute—

“May, 1969” (11)

Page 2, line 38,—

for “May, 1966” substitute—

“May, 1969” (12)

सभापति महोदय, मेरे संशोधन नम्बर 11 और 12 खण्ड (5) में हैं जिसमें कहा गया है कि किसी व्यापारी की टर्न ओवर तय करने के लिए क्या विधि अपनायी जायगी। नए खण्ड (8A) में वह फारमूला दिया गया है जिसके अनुसार किसी व्यापारी का टर्न ओवर बिक्री करके लिए डिट-

[Shri Shiva Chandra Jha]

रबिन किया जायगा ऐन्टीमेंट सेल प्राइस में से फौरमूले के अनुसार डिडक्शन करके। दूसरी जो सेल प्राइस है, सेल पर तमाम बिक्री का हिसाब किया जायगा, उसके मुताबिक कितने समय तक का हिसाब किया जायगा, उसके मुतालिक है।

"...the sale price of all goods returned to the dealer by the purchasers of such goods,

- (i) within a period of three months from the date of delivery of the goods, in the case of goods returned before the 14th day of May, 1966 : "

14 मई, 1966 के तीन महीने पहले तक की कीमत के ऊपर यह हिसाब लगाया जायगा कि उस डीलर की कितनी बिक्री हुई। और 14 मई, 1969 के 6 महीने बाद की जो कीमत होगी उस के मुताबिक डीलर की तमाम बिक्री का हिसाब किया जायगा। 1966 के पहले तीन महीने और 1969 के 6 महीने बाद तक। लेकिन यह 1966 से 1969 के बीच तीन साल का कौन हिसाब होगा, किस प्राइस का? यह तीन साल के लिए किस रूप में लागू होगा। इसीलिए मई, 1966 जो है उसकी जगह पर मैं चाहता हूँ कि सरकार बदल कर मई 1969 कर दे।

Page 2, line 35, for "May, 1966"
substitute

"May, 1969"

Page 2, line 38, for "May, 1966"
substitute

"May, 1969"

जहाँ जहाँ मई, 1966 है वहाँ वहाँ मई 1969 कर दिया जाय, तब तो मतलब वाली बात हो जाती है। 14 मई, 1969 के तीन महीने पहले तक जो बिक्री होगी वह जोड़ी जाएगी और 14 मई, 1969 के छः महीने बाद तक जो बिक्री होगी वह जोड़ी जायेगी। लेकिन 1966 और 1969 के बीच के तीन सालों का क्या होगा ?

इसलिए मेरा यह संशोधन यह है कि 14 मई, 1966 की जगह पर 14 मई, 1969 कर दिया जाये।

SHRI P. C. SETHI : Sir, as far as this particular amendment is concerned, the position is that the deductions are allowed if the goods were returned prior to 14th May, 1966, within three months from the date of delivery and after the date, within six months from the date of delivery. The reason for this is that the rules were amended on 14-5-1966 whereby a longer period of six months was provided for the return of the goods. What we are now doing is to incorporate in the law the rules with reference to which the assessments have been made.

As a matter of fact, this is in spite of the fact that previously it was three months. Now, according to this legal provision, we are making it six months. If the amendments proposed are accepted, it will cause confusion and result in the reopening of many assessments. It will also be contrary to the rules with reference to which assessments have been made so far. The amendments proposed, if accepted, would be to the detriment of the dealers. As against the period of six months available now, there will have to be deductions in respect of goods returned during the period 14th May, 1966 to 14th May, 1969, which would be available only if the goods were returned within three months from the date of the delivery of the goods.

Therefore, on these grounds, it would be difficult to accept the amendments brought forward by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN : I shall now put the amendments to the vote.

Amendments Nos. 11 & 12 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :
"That clause 5 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clause 6—(Substitution of new section for section 9)

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : I
move :

Page 3, line 44, *add* at the end—

“after due consultation with that State.” (13)

Page 3, line 48, *after* “assigned” *insert*—

“and given” (14)

Page 3, line 48, *omit* “and shall be retained by it” (15)

मेरे यह एमेंडमेंट है क्लॉज नं० 6 के ऊपर, जिस में यह कहा गया है कि :

“Provided that if in any State or part thereof, there is no general sales tax law in force, the Central Government may, by rules made in this behalf, make necessary provision for all or any of the matters specified in this sub-section.”

यानी जिस राज्य में सेल्स टैक्स का कानून नहीं है वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट इस ऐक्ट के मुताबिक ऐक्ट बनायेगी। इसमें इतना जोड़ देना चाहता हूँ कि :

“after due consultation with that State.”

जिस राज्य में सेल्स टैक्स नहीं है जब उसके लिए केन्द्रीय सरकार कदम उठायेगी कानून बनाने के लिए, तो उसमें मेरा संशोधन यह है कि वह जरूर उस स्टेट को कन्सल्ट करेगी।

चौदह नम्बर की जो मेरी एमेंडमेंट है वह सब क्लॉज तीन में है। क्लॉज छः की सब क्लॉज तीन में यह है

“The proceeds in any financial year of any tax, including any penalty

levied and collected under this Act in any State (other than a Union territory) on behalf of the Government of India shall be assigned to that State and shall be retained by it.”

यहां पर एसाइन के बाद मैं चाहता हूँ कि शब्द एंड गिवन जोड़ दिये जायें। जो यह लिखा हुआ है कि एंड शैल बी रिटेंड बाई इट, इनको उड़ा दिया जाना चाहिये। राज्य सरकार के बिहाफ पर जो कर आपने इकट्ठा किया है और जिस हिसाब से किया है उसमें से केन्द्र का जो भाग है, उसको रखकर यह कहा गया है कि एसाइन वह रुपया राज्य सरकार को किया जाएगा। मतलब यह है कि राज्य को देगे नहीं। मैं चाहता हूँ कि इसमें एसायन एंड गिवन होना चाहिये। हिसाब लगाकर जितना राज्य सरकार का बनता है, वह उसको मिल जाना चाहिये। राज्य सरकार के नाम पर केन्द्र इसको रखे नहीं बल्कि हिसाब करके अपनी मेहनत का रुपया काट कर, जो कर्मचारी उसके लगते हैं इस टैक्स को इकट्ठा करने के लिए, उन सब के खर्चे काटकर जो राज्य सरकार का बनता है हिसाब करके उसको आप दे दें। अपने पास उसको रखें नहीं।

मैंने यही चाहा है कि जिन राज्यों में सेल्स टैक्स कानून नहीं है उसके बारे में अगर केन्द्रीय सरकार कदम बढ़ाती है तो पहले उसको सम्बन्धित राज्य सरकार को कंसल्ट कर लेना चाहिये। बिना कंसल्ट किये हुए कदम नहीं उठाना चाहिये।

दूसरे मैं यह चाहता हूँ कि जब टैक्स आप इकट्ठा कर लें तो आप एसाइन ही न करें बल्कि उसको उसका हिस्सा दे दें। उसको केन्द्र अपने पास न रखे। इससे राज्य और केन्द्र के जो रिश्ते हैं वे अच्छे होंगे और इन रिश्तों के बिगड़ने की जो सम्भावना होती है, वह खत्म होगी। दोनों के सम्बन्ध अच्छे होंगे।

SHRI P. C. SETHI : As far as this particular provision is concerned, it is on the statute-book since 1958 and we never had the occasion to invoke it. But there are certain territories where there is no local sales tax—for example, Tripura, Dadra Nagar-Haveli, Andaman and Nicobar Islands etc. Although it is not our intention to introduce the sales tax there, at the same time, it would be wise, when we are bringing forward a measure like this, to have power in our hands so that whenever Government considers it necessary it may have the authority to introduce sales tax in such areas where the Government thinks it proper. Therefore, I can only say at this stage that it has been there on the statute-book from 1958 and we had no occasion to invoke it. Therefore, Sir, there could be no harm in having this authority with the Central Government at this stage.

MR. CHAIRMAN : I shall put the amendments to the vote of the House.

The Amendments 13, 14 and 15 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN . The question is,

“That clause 6 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 6 was added to the Bill.

श्री स० मो० बनर्जी : इस वक्त हम बहुत ही इम्पार्टेंट बिल को डिस्कस कर रहे हैं। जब 31 से 51 रुपये करने वाला बिल आया था तो आप जानते हैं कि कितने माननीय सदस्य यहाँ उपस्थित थे। थर्ड रीडिंग स्टेज पर हमको बोलने तक नहीं दिया गया। इस बिल से लाखों छोटे-छोटे बिजनेसमैन एफेक्ट होंगे। इस वक्त हाउस में कोरम नहीं है। कोरम होना चाहिये। मेरा सिर शर्म से झुक गया जब हमको बोलने नहीं दिया गया।

MR. CHAIRMAN : The bell is being rung...Now there is quorum.

The question is :

“That clause 7 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clause 8 was added to the Bill.

Clause 9—Validation of assessments etc.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : I beg to move :

Page 4, line 38,—

add at the end—

“Provided there had been malpractice or misuse of such power by the concerned authority”(18)

SHRI OM PRAKASH TYAGI : I beg to move :

Page 4, line 38,—

add at the end—

“provided there had been malpractice or misuse of power by the concerned authority” (29)

SHRI LOBO PRABHU : I beg to move :

Page 4, line 23,—

for “notwithstanding any thing contained in”

substitute “Subject to”(16)

Page 4, line 37,—

for “maintained or continued” substitute “instituted”(17)

Page 4,—

omit lines 40 and 41.(19)

SHRI LOBO PRABHU : Section 9 reads as follows :

“Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court or any authority to the contrary, the assessments will stand.”

This involves two issues. Firstly, by this section you frustrate the judgments of courts which are made on your own laws,

[Shri Lobo Prabhu]

the law passed in 1958 and 1956. Is it proper, is it constitutional for you to frustrate your own judges ?

Secondly, when a party has taken the trouble, incurred the expenditure and obtained the judgment in his favour, is it fair for you after several years to say that your assessment stands notwithstanding his expenditure and trouble, not to speak of his anxiety ? These are very serious issues. You claim to be the government for the people ; you claim to be a democratic government. When there are thousands and thousands of people involved in this, you are denying them first the authority of law in respect of their rights and, secondly, you are denying them the fruits of their litigation. I would, therefore, suggest that in place of the word "Notwithstanding" you substitute "Subject to" so that you can make an exception in respect of those decrees and orders which have been in favour of the parties. The amount involved will be small, but the effect of it both moral and political will be large indeed, and I do hope that although you have resisted all amendments, you will accept this one small amendment.

My next amendment is to the same clause. You say :

"No suit or other proceedings shall be maintained or continued in any court or before any authority for the refund of any such tax."

Here again, the party has paid court fees, engaged lawyers and you go and tell him at this stage that his suit cannot be proceeded further. When on the basis of your own law and judgment, on the basis of the judgment in *Yadalam* in 1964 and the continuing judgments right up to the Supreme Court judgment in *Pothan Joseph's* case, the affected parties go to court, are you justified in saying that the suits which have been instituted are barred and the parties are not in any way to be compensated ? I would suggest only this to you that in respect of these suits, you may at least meet the costs incurred by the parties even if you are proceeding with your assessments. This is the minimum you can do consistently with justice and law.

My third amendment is about (c), that no court shall enforce any decree or order directing the refund of any such tax. I have already argued about that when I spoke on clause 2. I do hope that when there is a decree, you will respect that decree and you will respect the law. We are passing through a very difficult time. If you set an example of not respecting the law, you cannot expect the communists and others to do better. It is upto you to show respect to the law in what you do and in what you legislate.

श्री शिवचन्द्र मा : सभापति जी, मेरा संशोधन नं० 18 है और क्लॉज 9 (बी) जो है :

"(b) no suit or other proceedings shall be maintained or continued in any court or before any authority for the refund of any such tax ;"

इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यह इसमें जोड़ दिया जाय :

"Provided there had been malpractice or misuse of such power by the concerned authority."

बात यह है कि इस सेल्सटैक्स को रिअलाइज करने के लिए जो अधिकारी रहेंगे जिस रेट से वह टैक्स लगाएंगे जिम तरह से वमूल करेंगे टैक्स को डीलर्स से, व्यापारियों से उसके मुताल्लिक कहा है कि

"no suit or other proceedings shall be maintained or continued in any court or before any authority for the refund of any such tax ;"

यइ बिलकुल जजमेंट के खिलाफ है। आप क्या समझते हैं कि टैक्स कलेक्टरस या हिन्दुस्तान का कोई अफसर या कर्मचारी कोई भी हो वह दूध का घोया हुआ है ? यही तो हमको बीमारी है। जोर जुल्म से, डरा धमका कर, धांधली करके जो भी जनता को सताता है, उसके साथ जुल्म करता है वह हमें रोकना है। यह जो इनका अफसर रहेगा यदि वह ज्यादा रेट पर हिसाब

करके टैक्स वसूल करता है तो क्या जनता को हक नहीं है कि वह उसके मुताल्लिक केस दायर करे? जो उसको देना चाहिए वह तो उस ने दिया ही, उसके अलावा इनके जो अफसर हैं उनके गलत व्यवहार के कारण, उस को ज्यादा देना पड़ा है तो क्या जनतंत्र यही कहता है कि वह उसके खिलाफ कोर्ट में न जाय? संविधान का दर्शन यह कहता है, आम समाज का और समाजवाद का दर्शन यह कहता है कि हर नागरिक को हक है कि वह हर जोर जुल्म और भ्रत्याचार के खिलाफ टक्कर लगाए चाहे कोर्ट में जा कर लगाए चाहे कानून के जरिए और तरह से लगाए। इसीलिए मेरा संशोधन है। यहां पर कहा है कि कोई मुकदमा उस एथारिटी पर नहीं चलाया जाएगा। मेरा कहना है कि जब उस अफसर ने जोर जुल्म किया, डराया धमकाया, किसी नाजायज रास्ते का इस्तेमाल किया तो उस व्यापारी को पूरा हक होना चाहिए कि वह इस बात को कोर्ट के सामने लाए और कचहरी के जरिए अपने साथ इन्साफ कराए।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : सभापति महोदय, इस बिल में यही एक सबसे बड़ी क्लज है...

श्री भोलू प्रसाद (बांसगांव) : सभापति जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हम लोग जो प्रश्न करते हैं, अंग्रेजी का उत्तर अंग्रेजी में दिया जाय तो हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन हिन्दी के प्रश्नों हिन्दी में उत्तर दिये जाने चाहिए...

सभापति महोदय : यह सवाल इस समय यहां नहीं है। यह इस विषय से सम्बन्धित नहीं है। इसलिए प्वाइंट आफ आर्डर को मैं ओवर रूल करता हूँ। आप दफ्तर को लिख कर भेज दीजिए।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : सभापति जी, इस समय सबसे बड़ी समस्या इस देश में एक है और वह है काले धन की और सेल्स टैक्स का यह जो अमेंटमेंट बिल आया है

उसी के सुधार के दृष्टिकोण से आया है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में करोड़ों अरबों रुपया काले धन के रूप में पड़ा हुआ है। उसका मूल कारण यह है कि सेल्स टैक्स लगाने का ढंग बड़ा दोषपूर्ण है। सेल्स टैक्स आफिसर के सामने दुकानदार अपना रजिस्टर ले कर आता है, अपना खाता वह दिखाता है, जितनी इन्कम वह दिखाता है, उस पर टैक्स न लगा कर अपने अनुमान से टैक्स लगा देते हैं। परिणाम यह हुआ है कि दुकानदार दो खाते बना लेते हैं—एक सरकार को दिखाने के लिए और दूसरा अपने लिए। सल्ज टैक्स आफिसर जो मनमाने ढंग से टैक्स लगाते हैं, इन को रोकनेवाला कोई नहीं है—आज इसका परिणाम यह हुआ है कि करोड़ों-अरबों रुपया काले धन के रूप में चला गया है। इस देश में इस समय दो प्रकार के धन हैं—एक पी० एल० 480 का और दूसरा यह काला धन, जो यहां पर वस्तुओं के मूल्य नीचे नहीं आने देते, स्थिर नहीं होने देते।

सभापति महोदय, क्लज 9 में जो (ए) सब-क्लज है, उसमें कहा गया है—

- (a) all acts, proceedings or things done or taken by the Government or by any officer of the Government or by any other authority in connection with the assessment, re-assessment, levy or collection of such tax shall, far all purposes, be deemed to be, and to have always been, done or taken in accordance with law."

इस के अर्थ यह होता है कि आप एक चोरी को पकड़ने के लिए दूसरी को संरक्षण देते हैं। यह कैसे हो सकता है। सेल्ज टैक्स आफिसर अगर किसी के असेसमेंट में गलत काम करता है, मनमाना टैक्स लगाता है तो आप अपने चोर को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं और दूसरे चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सभापति महोदय, वर्तमान समय में गवर्नमेंट के आफिसर भी चोर हैं और दुकानदार भी चोर हैं—पूरा का

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

पूरा अमला चोर बना कर खड़ा कर दिया है और इसका कारण केवल सरकार है, इसके कानून के दोष के कारण ऐसा है। आज सरकार की मशीनरी करप्ट हो गई है। अगर आप चोरी रोकना चाहते हैं तो दोनों तरफ की चोरी को रोकें होना तो यह चाहिए कि कानून की दृष्टि में दुकानदार जो खाता लेकर आता है, जितनी आमदनी दिखाता है, उस पर सेल्ज टैक्स लगाइये, अगर कोई आदमी ठीक आमदनी प्रकट नहीं करता और गवर्नमेंट उसे पकड़ लेती है, तो फिर उसको साधारण सजा नहीं होनी चाहिये, कम से कम दो-चार साल के लिए वह जेल जाय, इससे सब दुकानदार ठीक हो जायेंगे।

इस समय क्या घांथली चल रही है? सेल्ज टैक्स आफिसर मनमाना 10 गुना, 20 गुना सेल्ज टैक्स लगा देते हैं और फिर पार्टी से पूछते हैं—बोलो, क्या हाल है। पार्टी से बीच में पैसा ले लेते हैं और इस तरह से सेल्ज टैक्स का नुकसान होता है। यह जो लूट चल रही है, आफिसरजं बेलगाम बन रहे हैं, यह करप्टन नहीं रुकेगा, बेइमानी नहीं रुकेगी, काला धन नहीं रुकेगा। आज जिस प्रकार से आपने दुकानदार को बांध दिया है, यहां सुनवाई नहीं होगी, वहां सुनवाई नहीं होगी, मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने आफिसरजं को भी डर में रखिये—अगर तुमने गठन काम किया तो तुम्हारे खिलाफ भी सुनवाई हो सकेगी। इसलिए मेरा मुझाव यह है कि...

श्री सीताराम केसरी (कटिहार) : काला धन कैसा होता है ?

श्री ओम प्रकाश त्यागी : जैसा धन आप कमाते हैं। आपको खूब पता है कि काला धन कैसे पैदा होता है। मैं तो गांध का किसान आदमी हूँ, लेकिन मैं अपनी बीमारी को खूब जानता हूँ।

आप हर दुकानदार, हर आदमी को चोर बना रहे हैं, हर एक के पास काला धन है।

बहुत कम आदमी हैं जो ईमानदारी से चलना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको भी नहीं चलने देना चाहती।

श्री स० मो० बनर्जी : काले धन का रंग काला होता है, लेकिन सफेद टोपी के पीछे छिपाये रहते हैं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : सभापति महोदय, मैं खास तौर से गवर्नमेंट से प्रार्थना करना चाहता हूँ—मेरा लक्ष्य इस क्लाइ का विरोध करने का विचकूल नहीं है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और जो बायें मेरे पास पहुंचती हैं, उनके अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूँ, अगर आप इस बिल के पीछे अपने लक्ष्य की पूर्ति करना चाहते हैं तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि दोनों तरफ से जो बीमारियां हैं उनको रोकिये। जो विजनेसमेन सेल्स टैक्स की चोरी करते हैं, बेइमानी करते हैं उनको रोकने के लिए आपने सेल्स टैक्स आफिसर रखे हैं, एक बहुत बड़ा कानून बनाया है उसी तरह से उन आफिसरस को भी रोकने के लिए आप कोई धारा रखिए जोकि दुकानदारों और विजनेसमेन को सेल्स टैक्स की चोरी करने के लिए मजबूर करते हैं। आपने उनके लिए कोई नियम नहीं बनाया है, उनको बेलगाम होकर सेल्स टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया है और इस कानून के द्वारा उनके खिलाफ शिकायत करने की गुंजायश भी नहीं छोड़ी है। किसी को गोली मारने से पहले या फांसी पर चढ़ाने से पहले उसको अपील करने का तो मौका देना चाहिए। आपने इसमें अपील की बात को भी समाप्त कर दिया है। इसलिए मैं इसके साथ यह जुड़वाना चाहता हूँ :

Provided there has been malpractice or misuse of power by the concerned authority.

अगर उसने ऐसा किया है तो किसी आदमी को उनके खिलाफ शिकायत करने का मौका देना चाहिए। न्याय और जस्टिस देना सरकार का

काम है। भारतवर्ष के संविधान ने हर आदमी को अधिकार दिया है कि वह अपनी फरियाद कर सके और न्याय प्राप्त कर सके लेकिन इस धारा के अनुसार आपने न्याय से इनकार किया है।

SHRI P. C. SETHI : Hon. member, Shri Lobo Prabhu has two amendments. He is a very experienced person and well-versed in trade. If I accept his amendments, the result would be that the very purpose of bringing this Bill before this House would be completely null and void. His amendment, for example in clause 9, is to validate, if there is any judgment, then we should accept this. It is on account of a judgment of the Supreme Court that we have brought forth this legislation before the House. If we accept the amendment of the hon Member, Shri Lobo Prabhu, the very object of the Bill will be defeated.

SHRI S. M. BANERJEE : Upto this time they have moved 234 amendments, but nothing has been accepted by the Government.

SHRI P. C. SETHI : With regard to his second amendment, I would like to say that there are already so many cases pending in various courts and various High Courts in the various States and if the second amendment is accepted, then in spite of the fact that after the Supreme Court judgment we have brought forward this legislation before the House which the House may pass, if there is any judgment with regard to this particular item from any High Court, then we should not put any bar there. Therefore, it is difficult for me to accept the amendments moved by Mr. Lobo Prabhu.

As far as what hon. member Shri Shiva Chandra Jha and hon member Shri Tyagi said, they are very valid points. What we are trying to seek here is in view of the Supreme Court judgment where they have described the manner as existed in the State. Therefore, in spite of the fact that the intention of the legislature was to apply the manner as described by the Act, we have, according

to the judgment, to go by the manner prescribed by the particular State Act. Similarly, with regard to the computation of the tax, according to the Supreme Court judgment we have to go by the method provided for computation of tax in a particular State and not as provided in the particular Act of 1956 and further amended in 1958. Therefore, to that extent we have corrected it. But the hon Members, Shri Jha and Shri Tyagi have brought before the House very valid points. Suppose there are some mistakes of calculations in the assessment of tax. As far as any mistake in the assessment of tax is concerned, there are procedures available and according to those procedures the mistakes in the calculation would be set right. It is only with regard to those legal provisions that we have brought forth this measure and if there are any mistakes in the calculation of tax—suppose the tax accruable is Rs. 100 and somebody has calculated it as Rs. 130, it is a mathematical mistake and certainly it can be corrected by procedural methods. If the hon Member has any case in view, it can be certainly brought to the notice of the Government and we will ask the respective Government to rectify the mistake.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : अमेंडमेंट में किस ने गलती की है। जो मैथिली कौन्सिलेशन में गलती हो, यह बात अलग है। एक आदमी अन्दाज से ही गलत लगा रहा है टैक्स, अगर किसी आदमी ने अमेंडमेंट ही गलत किया है उस के खिलाफ आप क्यों नहीं मौका देते हैं जनता को जांच करने का और केस करने का ?

श्री शिव चन्द्र झा : हर सम्भावना रहती है कि वह अफसर डरा घमका कर जुल्मी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या नागरिक को कोर्ट में जाने का हक नहीं है ?

श्री यशबन्त शर्मा : मुझे मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ खींचना है कि इस प्रकार की गुंजाइश और व्यवस्थायें हैं जहां सरकारी कर्मचारियों की ओर से बिक्री कर के सम्बन्ध में जो नाप तौल कर के व्यापारियों पर लागू करते

[श्री यज्ञदत्त शर्मा]

हैं। अगर उनके लिए प्रोसीजर के अन्दर इस प्रकार की गुंजायण है जहाँ उनकी गलतियों का सुधार किया जा सकता है या अपील की जा सकती है, ये जो सुविधायें हैं वे डिपार्टमेंट के अन्दर हो हैं। कोर्ट आफ ला में नहीं हैं। नतीजा यह है कि सारी नौकरशाही ऊपर से नीचे तक एक ऐमा क्लीक बन जाती है कि जहाँ व्यापारियों को राह नही मिलती। सभी जगह एक ही प्रकार की मनोवृत्ति काम करती है, इस लिये जहाँ इस प्रकार की और भ्रष्टाचार की मनोवृत्ति काम करती है, मैं यह नहीं कहता कि बेईमान व्यापारी के साथ कोई रियायत की जाये, लेकिन जहाँ नौकरशाही की ओर से गड़बड़ होती है उसके लिए तो कोई गुंजायश रहनी चाहिये।

SHRI P. C. SETHI : This tax is levied on movements of goods from one State to another and the rate is also prescribed, 3 per cent, in the Bill before us. Cl. 8 already passed by us, we have stipulated what would be the formula for collection of the tax. We have provided it in 8 (a).

17 37 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

This Bill is only with regard to the interpretation of the Supreme Court regarding the manner and the computation of the tax.

As far as any mistakes are concerned, there are already provisions for appeal for rectification provided appeal is made in time and rectification procedure gone through in time and is not time-barred. So for genuine mistakes, procedures are available for rectification. It is only to fill up the legal lacuna that this Bill has been brought forward. Therefore, it is difficult for me to accept the amendments moved.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall now put all the amendments together to vote.

Amendment Nos. 16 to 19 and 29 were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That clause 9 stand part of the Bill."
The motion was adopted.

Clause 9 was added to the Bill.

Clause 10—(Exemption from liability to pay tax in certain cases)

SHRI LOBO PRABHU : I move :

Page 5,—

omit lines 12 to 15. (20)

Clause 10 provides : "Where any sale of goods in the course of inter-State trade or commerce has been effected during the period between the 10th day of November, 1964 and the 9th day of June, 1969 ...no such tax could have been levied or collected....." I should like the Minister to realise how many transactions are involved and how many sales tax assessments will have to be reopened over a period of four years? Has the Minister considered what extra work will be involved and what extra staff will be necessary? All for what purpose? After the 1964 Daddalam case it was no secret that tax was not due. In that case who would pay tax if it was demanded? It is impossible to believe that those who sold the thing would pay tax. You are entering into an area where there is very little to be realised. The time and the trouble you are wasting on this is not at all justified. You are trying to recover tax from some partners. They have no books to prove. You are not realising that when there is no tax there must be price adjustment and less is paid because no tax is being paid. Are you going to make tax adjustments where the party cannot prove that tax had not been collected. I may point out that nowhere is it insisted that the negative should be proved. You have to prove a positive. What are you going to do? Are you going to produce oral witnesses or books which may not contain these statements; it will be foolish to produce such a book,

So, I request the hon. Minister to apply his mind. I give many reasons and he gives short replies which are many a time not relevant at all. You have no possibility of any one having collected this tax. In those circumstances to begin to open up all those cases and to cast on the traders the burden of proof that no tax has been paid is unfair, if not absurd. They should either delete clause 10, or at least clause 10(2) which places on the trader the burden of proof that no tax has been paid.

SHRI P. C. SETHI : The hon. Member is advancing a very novel argument, as far as the theory of tax collection is concerned. If a person says he is not liable to pay tax, the onus of proof devolves upon him. According to him it should be for the department to say if he has collected tax. It is for him to say if he has collected; if he has not collected and the tax collected does not get entered in the account books it is a different matter. But then accounts are of two kinds; one is for one purpose and another is for another purpose. If there is one genuine account book where all entries are properly made, then the tax collected would find an entry. It is easy for him to prove that he has collected or not collected the tax. The onus devolves upon the party who is asking for the tax exemption and not on the department who are out to collect the tax.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I put amendment No. 20 to the vote of the House.

Amendment No. 20 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

“That clause 10 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 10 was added to the Bill.

Clause 11 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

SHRI P. C. SETHI : Sir, I beg to move :

“That the Bill be passed.”

श्री सुलशीदास जाधव (बारामती) : मुझे दो तीन बातें मंत्री महोदय से कहनी हैं। स्टेट्स में वन प्वाइंट, टू प्वाइंट इत्यादि रीति से यह टैक्स लगता है। हर प्रान्त सेल्ज टैक्स लेता है और उसके साथ साथ सेंटर का भी सेल्ज टैक्स होता है। इससे एकार्टिंग में और रबीद देने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है। मैं चाहता हूँ कि सेल्ज टैक्स भी आप एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ वसूल कर लिया करें और जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी में से आप स्टेट्स को हिस्सा देते हैं उसी तरह से इसमें से भी दे दिया करें। जितना सेल्ज टैक्स वसूल होता है उसका आप हिसाब कर लें और अगर हो सके तो एक्साइज ड्यूटी उसी हिसाब से बढ़ा दें।

आजकल किसी प्रान्त में सिंगल प्वाइंट सेल्ज टैक्स और किसी में डबल प्वाइंट सेल्ज टैक्स है। मैं चाहता हूँ कि जिन प्रान्तों में डबल प्वाइंट सेल्ज टैक्स है वहां भी आप सिंगल प्वाइंट सेल्ज टैक्स रखें। अगर आप इसको एक्साइज ड्यूटी में मर्ज न कर सकें तो ऐसा आप कर सकते हैं।

सेल्ज टैक्स वहीं बिठाया जाना चाहिए जहां माल तैयार होता है, जहां इसका उत्पादन होता है, जहां प्रोडक्शन होता है। उस अवस्था में लोगों को तकलीफ नहीं होगी। जिस तरह से वहां पर आप एक्साइज ड्यूटी बिठाते हैं उसी तरह से उसके साथ-साथ आप सेल्ज टैक्स बिठा दें। वसूली करने में जो दिक्कत होती है उस अवस्था में वह नहीं होगी। इससे छोटे तथा बड़े दूकानदार जो उनको तकलीफ होती है, वह नहीं होगी। जो कंज्यूमर है उसको भी जो तकलीफ होती है उससे वह बच जायेगा। लोगों का कहना यह है कि हम से टैक्स दो रुपये अधिक ले लो लेकिन यह जो एकार्टिंग का

[श्री तुलशीदास जाधव]

भगड़ा है इसमें हम को न डालो। इसके लिए उनको एकाउन्टे रखना पड़ता है, एक दो क्लर्क रखने पड़ते हैं, एकाउन्ट बुक रखती पड़ती हैं। कभी कोई अफसर आ जाता है कभी कोई। लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं लेकिन उसको वसूल करने के लिये आप सीधा और सरल तरीका क्यों नहीं अपनाते हैं? जब मैं महाराष्ट्र स्टेट में एम० एन्० ए० था तब जीवराज मेहता जी ने सिगल प्वाइंट, डबल प्वाइंट करके सेल्ज टैक्स बिठाया था। हम ने उनसे कहा था कि आप इसको एक्साइज ड्यूटी में मर्ज क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने कहा था कि इसके लिये सेंटर को राजी करना होगा। उस वक्त जो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने सेंटर के साथ चर्चा करके इसको एक्साइज ड्यूटी में डलवा दिया था और लोग तकलीफ से बच गये थे। अगर आप को इससे बीस करोड़ मिलता है तो लोग कहते हैं कि आप पांच करोड़ और ले लो लेकिन जो हमको तकलीफ होती है उससे हमको बचाओ। अगर बकरा काटना हो तो एक दम छुरी लेकर उसको काट देना चाहिए न कि बुकलुन, बुकलुन करके। इस तरह से मारना ठीक नहीं है। जो आपको वसूल करना है उस को सरल तरीके से आप वसूल करें ताकि लोगों को तकलीफ न हो।

श्री यशवन्त शर्मा : जो मैं पहले कह चुका हूँ उसी को मैं दोहराना चाहता हूँ। सरकार ने एक विशेष प्रकार का कर लगाया है जिसके द्वारा वह धन लेना चाहती है। अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि अध्यादेश हम इसलिए लाये कि जो बिक्री कर राज्यों में लिया जाता है, इंटर स्टेट सेल्स टैक्स, कानूनी अड़चन आने के कारण, उसको ठीक करना हमारे लिए जरूरी हो गया था। अब उसी अध्यादेश को कानून की शक्ल दी जा रही है। करों की वसूली का जो ढांचा है, सारे मुद्दे तय करके कितने कर लगेगे, उनसे कितनी आमदनी होगी, वह स्टेट्स का ढांचा है और उन्हीं पर आप निर्भर करते हैं।

परन्तु आज तो इससे व्यापारी को कठिनाई होती है। सरकार के डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन एकाउंट्स मेनटेन नहीं करते हैं। सारे एकाउंट्स व्यापारी को मेनटेन करने पड़ते हैं। सारे कर व्यापारी वसूल करता है, लेकिन सरकार के बेईमान अफसर—मुझे खेद है कि इस शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है—व्यापारी को हैरास करते हैं, दस बारह दिन तक बुक्स ले कर उस के सिर पर बैठे रहते हैं और गलत एसेसमेंट कर के उस से पैसा वसूल करने के लिए दबाव डालते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर सरकार एक लेबल पर, सिगल पायंट पर, आर्गनाइज्ड इंडस्ट्रीज के प्राइवशन पायंट पर, एक्साइज ड्यूटी के रूप में, या किसी भी रूप में, एक बार कर लगा ले और बाकी व्यापारियों को इस भ्रष्ट से मुक्त कर दे, तो सरकार को ज्यादा पैसा मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन की करप्शन दूर होगी और टैक्सों के नेचर में सिम्प्लिसिटी आयेगी। मंत्री महोदय इस मुद्दा पर विचार करें। वह यह न सोचें कि यह मुद्दा आपोजीशन की ओर से दिया जा रहा है, बल्कि वह टैक्स सिस्टम को सिम्प्लीफाई करने की दृष्टि से इस मुद्दा पर अवश्य विचार करें।

श्री कंवर लाल गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री शर्मा, ने जो कुछ कहा है, मैं उसका समर्थन करना चाहता हूँ। सरकार इस समय कपड़ा, तम्बाकू और शूगर पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है। उसके परिणामस्वरूप टैक्स में चोरी नहीं होती है, व्यापारी और कनज्यूमर दोनों को सुविधा होती है। लेकिन जहां सेल्ज टैक्स और इंटर-स्टेट सेल्ज टैक्स लगाया जाता है, वहां काफी मात्रा में चोरी होती है, सारी ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही खूब पैसा कमाती है, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा नुकसान होता है और दुकानदार तथा कनज्यूमर दोनों बहुत तंग होते हैं। मैं समझता हूँ कि सेल्ज टैक्स और इंटर-स्टेट सेल्ज टैक्स इस देश पर एक बहुत

बड़ी लानत है। मैं यह नहीं कहता कि आमदनी के उस सोर्स को बन्द कर दिया जाये। लेकिन जहाँ जहाँ भी सरकार इसके बदले एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है, वह वहाँ पर एक्साइज ड्यूटी लगाये। सरकार ने ग्राज तक अपना माइन्ड एप्लाइ नहीं किया है कि एक्साइज ड्यूटी किस किस जगह लगाई जा सकती है। जो कन्ट्रोल आइटम्स हैं, जो कारखाने में बनते हैं, उन पर तो एक्साइज ड्यूटी लगाई ही जा सकती है। यह सोर्स पर लगाई जा सकती है।

विभिन्न राज्यों में कहीं एक पायंट पर सेल्ज टैक्स है और कहीं दो पायंट पर, जिस से बड़ी गड़बड़ होती है। सरकार को राज्यों के चीफ़ मिनिस्टर्स से बात कर के सेल्ज टैक्स में यूनिफ़ामिटी लाने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। छोटे छोटे व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी लानत सेल्ज टैक्स और इन्टर-स्टेट सेल्ज टैक्स हैं। हमारी तरफ़ से पहले भी कई बार सवाल उठाए जाने पर मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि इस बारे में राज्य सरकारों से बात करनी पड़ेगी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से बात की गई है या नहीं।

दिल्ली एक डिस्ट्रिब्यूटिंग सेंटर है और इस लिए जहाँ का व्यापार तभी जिन्दा रह सकता है, जब जहाँ पर सेल्ज टैक्स और इन्टर-स्टेट सेल्ज टैक्स की दरें कम हों। आप को याद होगा कि इस बारे में यहाँ पर कुछ वर्ष पहले एक बड़ा भारी एजिटेशन चला था और पन्त जी ने यह विश्वास दिखाया था कि दिल्ली का डिस्ट्रिब्यूटिंग क्लैरिफ़र मेन्टेन किया जायेगा। वह विश्वास इस सदन में दिखाया गया था और वह रिकार्ड पर है। लेकिन यह दुख की बात है कि सरकार अपने वायदे को पूरा नहीं कर रही है। चूँकि यह एक स्टेट सबजेक्ट है, इसलिए यू 0 पी 0, पंजाब हरियाणा तथा आस

पास के अन्य राज्य अपने यहाँ सेल्ज टैक्स को कम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस के लिए हमें केंद्र से आज्ञा लेने की ज़रूरत पड़ती है। परिणाम यह है कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा हिस्सा व्यापार का दिल्ली से हट कर के दूसरी तरफ़ चला गया है और दिल्ली के लोगों को बड़ी भारी इस की चोट है। मैं चाहूँगा कि मंत्री महोदय इस की जांच कराएँ कि जो भी सेल्ज टैक्स आस पास के राज्यों में है दिल्ली में उससे एक परसेंट सेल्स टैक्स कम होना चाहिए जैसा कि पहले गृह मंत्री ने विश्वास दिलाया था।

इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूँगा कि मंत्री महोदय मेरे सुझाव पर विचार करेंगे।

SHRI S. M. BANERJEE : I would like to support Shri Tayagi and Shri Kanwar Lal Gupta. I remember that we raised this question in 1958 and when the sales tax was converted into excise duty on cloth the recovery was much more. Because, in that case, there is no evasion. It is almost impossible for an ordinary shop-keeper to keep a paid accountant and maintain all those books to evade duty. So, I would request him to consider this aspect and bring in an amendment in this session itself falling which in the next session.

SHRI P. C. SETHI : I have explained the position in the very beginning. As far as the replacement of the sales tax by Central excise is concerned, this question was examined in 1957 and in the National Development Council at that time, with the concurrence of the State Governments, it was decided that Central excise would be levied in respect of sugar, tobacco and cloth. In view of this agreement, excise is being levied on those commodities since then. After that the State Governments have been clamouring and making representations to the Central Government that even these commodities should be taken out of the purview of the excise duty and they should be left free to levy sales tax. Therefore, we

have handed over the entire matter to the Fifth Finance Commission and requested them to go into this matter thoroughly. The Fifth Finance Commission has submitted its report to the President and is under examination. Under article 281 of the Constitution, the report will have to come before both Houses of Parliament with the recommendations of government. We are considering changes in the 1958 Sales Tax Act. Therefore, by the time the report of the Finance Commission comes before the House our recommendations would also be available. So, I would not say that the suggestions given by the hon. Members are of no value. They are very valuable and they deserve consideration, but not now; they will be considered at that stage. Therefore, I request that the Bill may be adopted by the House.

श्री कंबर लाल गुप्त : दिल्ली के बारे में मैंने कहा कि दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट्यूटिंग कैरेक्टर है इसलिए यहां का सेल्स टैक्स आसपास के राज्यों से कम होना चाहिए। इस सम्बन्ध में आप दूसरे राज्यों से बात करेंगे।

SHRI P. C. SETHI : It is entirely for the local authorities to decide.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : The

rate of sales tax is to be decided by the centre and not by the Delhi Administration.

SHRI P. C. SETHI : In respect of those goods which are coming from outside Delhi, I am told that the Central sales tax in Delhi has been reduced from three to one per cent.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Thirty-eighth Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH) : I beg to present the Thirteenth Report of the Business Advisory Committee.

18 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, August 8, 1969, Sravana 17, 1891 (Saka)